● वर्ष-2
● अंक-144
रायपुर, शुक्रवार
03 फरवरी 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

ईडी के चालान में अवैध लेनदेन का ब्यौरा

अवैध उगाही की अनुमानित रक़म 540 बताते हुए 270 करोड़ की राशि का भुगतान ब्यौरा दिया

रायपुर। प्रदेश में कोयला के कारोबार से संबंधित अवैध उगाही को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने अनेक अधिकारियों और व्यापारियों को गिरफ्तार किया है जिसमें सूर्यकांत तिवारी, मुख्यमंत्री कार्यालय में सौम्या चौरसिया शामिल है। ईडी ने इस अवैध कमाई के जरिए की गई करोड़ों रुपए के लेनदेन के संबंध में एक चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया है। इस चालान में उप सचिव सौम्या चौरसिया और कोयला घोटाले से जुड़े अन्य लोगों के बीच पैसों के लेनदेन का उल्लेख किया गया है। ईडी ने इस चालान में यह भी बताया है कि, रक़म किन लोगों या समूह या संपत्तियों के निवेश खर्च की गई।

ईडी के चालान में उल्लेखित है कि, सूर्यकांत तिवारी का प्रभाव ऐसा था कि, वह तंत्र जिसकी जवाबदेही थी कि, वह इस गड़बड़ी को रोकता या कि नियंत्रित करता उसने आँखें मूंद ली थीं। ये कार्टेल इस कदर प्रभावी था कि परिवहन के नियमों में परिवर्तन 15 जुलाई 2020 हुआ और 30 जुलाई 2020 से 25 रुपए टन की वसुली शुरु हो गई। प्रवर्तन निदेशालय के चालान में निखिल चंद्राकर का नाम प्रमुखता से आया है। जिसके माध्यम से करोड़ों रुपए का लेनदेन होता था। ईडी ने चालान के प्रारंभिक पन्नों में ही अवैध उगाही से वसुली की अनुमानित रक़म 540 बताते हुए 270 करोड़ की राशि का भुगतान ब्यौरा संक्षिप्त में दिया है। इस ब्यौरे

के अनुसार इस अवैध उगाही में बेनामी संपत्ति जिसमें अचल सम्पत्ति और कोल वाशरी शामिल हैं उसमें 170 करोड़, सौम्या चौरसिया को मनीष उपाध्याय और जय के ज़रिए 36 करोड़, राजनैतिक दल के वरिष्ठ राजनेता को 52 करोड़, छत्तीसगढ़ के विधायकों को 4 करोड़, पूर्व विधायक और राजनेता को 6 करोड़, झारखंड भेजी गई राशि 5 करोड़, बैंगलोर भेजी गई राशि 4 करोड़ रुपए लिखी गई है।

पूछताछ का ब्यौरा भी दिया ईडी ने

प्रवर्तन निदेशालय ने चालान में अब तक इस प्रकरण की विवेचना में जारी नोटिस और परीक्षण में शामिल होने वाले व्यक्तियों के नाम भी शामिल किए हैं। ईडी ने सूर्यकांत तिवारी के परिजनों, सूर्यकांत तिवारी के कर्मचारियों, सूर्यत्व के व्यवसायिक साझेदारों, सौम्या चौरसिया और उनके संबंधित व्यक्तियों के साथ साथ खनिज विभाग से जुड़े चार अधिकारियों, पुलिस विभाग से जुड़े चार अधिकारियों जिनमें 3 आईपीएस और एक सिपाही शामिल है, दो ट्रांसपोर्टर और ईडी के नाम से कथित रुप से बीस लाख रुपए लेने वाले राजेश चौधरी और उसे बीस लाख देने वाले केंद्रीय जेल में बंद कोल वाशरी व्यवसायी सुनील अग्रवाल के रिश्तेदार का ज़िक्र है।

ईडी के इस चालान में पूरा विषय सौम्या चौरसिया की इस रैकेट में केंद्रीय और प्रमुख भुमिका स्थापित करने को लेकर केंद्रित है। ईडी ने इसी को स्थापित करने वाले प्रमाण इस चालान के साथ पेश किए हैं। इसके अतिरिक्त यह चालान कई नाम का ज़िक्र करता है लेकिन उसके बावजूद कई नाम का ज़िक्र इस चालान में नहीं है। यह माना जा रहा है कि उन बयान या नाम का ज़िक्र आने वाले अन्य पूरक चालान / चालानों में विस्तार से मिल सकता है।

केवल राजनैतिक षड्यंत्र है- फैज़ल रिज़वी

सौम्या चौरसिया के अधिवक्ता फैज़ल रिज़वी ने कहा है यह चालान ये सारे आरोप केवल राजनीति से प्रायोजित हैं। यह चालान केवल भानुमति का पिटारा है, इधर का इंट उधर का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा से ज़्यादा इस चालान को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। सौम्या चौरसिया पर केंद्रित इस चालान में जो तथ्य और बतौर साक्ष्यों ईडी ने कोर्ट को पेश किए हैं वे अदालत में कितने मज़बूत होंगे यह आने वाले समय में समझ आएगा। हमें न्यायालय से न्याय मिलेगा।

ईडी के चालान में उल्लेख क्या है

ईडी ने इस पूरे कार्टेल के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी को सौम्या चौरसिया से मिल रही ताक़त को साबित करने या कि संलिप्तता को प्रमाणित करने के लिए बहुत से अन्य अभिलेख और व्हाट्सएप चैट को पेश किया है। इसी के साथ ईडी ने पुलिस अधिकारी पारुल माथुर का बयान भी इसी परिप्रेक्ष्य में पेश किया है। ईडी ने पुलिस अधिकारी पारुल माथुर और सूर्यकांत तिवारी के बीच व्हाट्सएप चैट को लेकर सवाल पूछा तो उसके जवाब में पारुल के हवाले से दिए बयान में लिखा गया है

"....कोयले से संबंधित मैटर में हमें मौखिक रूप से निर्देश मिले थे कि कोई भी कार्यवाही से पहले श्रीमती सौम्या चौरसिया की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से अनुमति जरुरी है। इसी वजह से मैंने सूर्यकांत तिवारी को मैंने प्रह्लाद अग्रवाल का नाम एफआईआर में डालने / खोलने का मैसेज किया था। मैं प्रह्लाद अग्रवाल को नहीं जानती हूँ।"

इन दिनों

✍ शशांक शर्मा

धरना स्थल हटाने की मुहिम

सामान्य ज्ञान के प्रश्नपत्र में अगर कोई पूछे छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां है तो इसका उत्तर नवा रायपुर अटल नगर को माना जाएगा। लेकिन क्या वाकई नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है? नया रायपुर बसाने की कल्पना प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की थी। लेकिन उनकी सरकार चली गई, इसलिए डॉ रमन सिंह की सरकार ने कुछ फेरबदल करते हुए नया रायपुर का बसाने के कार्य को आगे बढ़ाया। 2010 में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के हाथों मंत्रालय और संचालनालय का उद्घाटन किया गया। इस बात को 12 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन नई राजधानी व्यवस्थित रुप से स्थापित नहीं हो सकी। अभी भी मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी पुराना रायपुर शहर में रहते है और यहीं से उनका काम भी चलता है। मंत्रालय में तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक कभी कभार ही जाते है। इसलिए बड़े अधिकारियों का भी काम मुख्यमंत्री का निवास कार्यालय और मंत्रियों के बंगले तक ही सीमित है। अब सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति को सरकार के सामने अपना दुखड़ा सुनाना है तो वह कहां जाए? देश में किसी भी व्यक्ति और संगठन को अपना दुखड़ा सुनाने और सरकार का विरोध करने का अधिकार संविधान ने दिया है। रायपुर में किसी भी तरह का आंदोलन करना है तो पहले मोतीबाग के सामने एक जगह निर्धारित थी। राज्य बनने के बाद आंदोलनों की संख्या बढ़ी तो मोती बाग से वह जगह बदलकर बूढ़ातालाब के सामने कर दी गई। यहां भी अब बड़ी संख्या में शासकीय अशासकीय संगठन और नागरिक विरोध करने आंदोलन करने यहां जमा होते है। भूपेश बघेल सरकार बनने के बाद अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित अनेक कर्मचारी संगठन यहां आए दिन प्रदर्शन करते है। स्वाभाविक है जगह छोटी पड़ती है और सड़क यातायात प्रभावित होती है। इससे परेशान होकर सदर बाजार के व्यापारियों ने इस आंदोलन स्थल को कहीं दूर ले जाने की मांग कर रहे है। रायपुर कलेक्टर ने उन्हें धमतरी रोड पर एक जगह मुहैया भी कराई है लेकिन वहां आंदोलनकारियों की आवाज कौन सुनेगा? जब हजारों की संख्या में आंदोलनकारी वहां पहुंचेंगे तो सड़क वहां भी जाम होगी। राजिम जगदलपुर मार्ग पर चलने वाले लोग और वाहन प्रभावित होंगे। सवाल धरनास्थल बदलने का नहीं है बल्कि सरकार को यह विचार करने का है कि उनके मार्फत काम करने वाले कर्मचारी लगातार आंदोलन क्यों कर रहे है? आंदोलन नहीं रोके जा सकते यह उनका अधिकार है। लेकिन सरकार इसका समाधान निकाल सकती है, यह सरकार का कर्तव्य है।

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजनांदगांव जिले के ग्राम भरेंगांव में आयोजित विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन में वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य, ऋण वितरण, वसूली इत्यादि कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समिति प्रबंधकों को सम्मानित किया।

17 वर्ष बाद नक्सलियों के कब्जे से मुक्त हुआ ये इलाका

■ अब एशिया का बड़ा इमली बाजार लेगा नई करवट

नई दिल्ली। केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन ने छत्तीसगढ़ पुलिस को साथ लेकर एक ऐसा मुश्किल कार्य, संभव कर दिखाया है जिसका इंतजार 2006 से हो रहा था। सफलता की इस दहलीज तक पहुंचने के लिए सीआरपीएफ को कई बड़े जोखिमों से गुजरना पड़ा है, नक्सलियों के अनेक हमलों को नाकाम किया गया। 17 वर्ष के दौरान नक्सलियों के खिलाफ सैंकड़ों छोटे-बड़े ऑपरेशन किए गए। 2006 से पहले इमली मार्केट को लेकर जिस क्षेत्र की एशिया में तूती बोलती थी, नक्सलियों ने

उसे बंद कर दिया था। सीआरपीएफ ने पुलिस के सहयोग से अब बीजापुर और दंतेवाड़ा को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग को नक्सलियों के कब्जे से मुक्त करा दिया है। इतना ही नहीं, महज तीस दिन के भीतर वहां पर दो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (एफओबी) भी स्थापित कर दिए। ये एफओबी बेडरे और कुंदर में तैयार किए गए हैं। इसके चलते एशिया का सबसे बड़ा इमली बाजार, अब एक नई करवट लेने की राह पर चल पड़ा है।

अधिकारियों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों के नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस को साथ लेकर माओवादियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है। सीआरपीएफ और राज्य पुलिस द्वारा, नक्सलियों को खदेड़ कर वहां फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (एफओबी) स्थापित किए जा रहे हैं। ये बेस न केवल रणनीतिक तौर पर, अपितु आसपास के क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों को भी पूरी तरह से खत्म करने में सहायक होंगे। इन कैंपों के जरिए स्थानीय निवासियों का भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लंबे समय तक नक्सलियों के प्रभाव को झेल चुके स्थानीय लोग, अब विकास का नया सवेरा देखना चाहते हैं। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में वहां बहुप्रतीक्षित विकासात्मक गतिविधियों को भी अब रफ्तार मिलने लगी है।

सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन ने लोकल पुलिस को साथ लेकर इमली बाजार के रूट को नक्सलियों के कब्जे से मुक्त कराने की रणनीति बनाई। 2006 के बाद जिला मुख्यालय बीजापुर और दंतेवाड़ा को जोड़ने वाला पुराना व्यापार मार्ग बाधित हो गया था। एशिया के सबसे बड़े इमली बाजार पर इसका व्यापक असर देखने को मिला। आंध्र प्रदेश, केरल व तमिलनाडु सहित कई क्षेत्रों की कनेक्टिविटी खत्म हो गई।

प्रमुख समाचार

हिंदू मक्कल काची के नेता की बेरहमी से हत्या, हथियारों से लैस भीड़ ने किया हमला

मदुरै। तमिलनाडु के मदुरै में एक हिंदूवादी संगठन के नेता की बेरहमी से हत्या करने की घटना सामने आई है। पीड़ित की पहचान मणिकंदन (41 वर्षीय) के रूप में हुई है, जो कि हिंदू मक्कल काची संगठन के पदाधिकारी थे। घटना बीती 31 जनवरी की है और हत्यारों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर के अनुसार, मणिकंदन, हिंदू मक्कल काची दक्षिण मदुरै के डिप्टी सेक्रेटरी थे और मदुरै के एमके नगर में उनकी ज्वैलरी की दुकान चलाते थे। मंगलवार रात को वह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों की भीड़ ने चाकू, दरांती और पत्थरों से उन पर पीछे से हमला बोल दिया। बेरहमी से हमला करने के बाद आरोपी मणिकंदन को घायल अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद मणिकंदन को अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

समान नागरिक संहिता लागू करने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं-कानून मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्र ने देश में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। मंत्री क्या सरकार के पास समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित करने की कोई योजना है के संबंध में एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। रिजिजू ने कहा कि विधि आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार समान नागरिक संहिता (ष्ष्ष्) से संबंधित मामला 22वें विधि आयोग द्वारा विचार के लिए लिया जा सकता है। इसलिए, समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने आगे जवाब दिया कि सरकार ने भारत के 21वें विधि आयोग से यूसीसी से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने और उस पर सिफारिशें करने का अनुरोध किया था। कानून मंत्री ने सूचित किया कि हालांकि, 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 को समाप्त हो गया। क्या सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने की दिशा में बढ़ रही है और क्या सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग जैसा एक स्वतंत्र नियामक स्थापित करने पर विचार कर रही है?

दिल्ली शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल आप ने गोवा चुनाव प्रचार के लिए किया-ईडी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कथित दिल्ली शराब घोटाले से मिले पैसों का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया। ईडी ने मामले में दायर चार्जशीट में कहा, इस रिश्वत के बारे में की गयी जांच में पता चला है कि अब तक इस फंड का कुछ हिस्सा आप के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया गया था। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे जिसमें आप ने दो सीटों पर जीत हासिल की थी। ईडी के मुताबिक, आप के सर्वे दल में शामिल स्वयंसेवकों को करीब 70 लाख रुपये का नकद भुगतान किया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि आप के संचार प्रभारी विजय नायर ने अभियान से संबंधित कार्य में शामिल कुछ लोगों को नकद में भुगतान प्राप्त करने के लिए कहा गया था।आगे कहा कि विजय नायर ने आप की ओर से वाईएसआरसीपी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुन्टा, अरविंदो फार्मा के निदेशक पी सरथ चंद्र रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता कलवकुंतला के एक समूह से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत प्राप्त की।

सुप्रीम कोर्ट में 1514 मामले 50 साल से हैं लंबित

नई दिल्ली। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में कोर्ट में पेंडिग केसों का जिक्र एक बार फिर से किया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि भारतीय उच्च न्यायालयों में 31 जनवरी, 2023 तक 50 से अधिक वर्षों से देश भर में 1,514 आपराधिक और दीवानी मामले लंबित हैं। रिजिजू ने कहा कि लंबित मामलों में से 1,511 सिविल मामले हैं, जबकि तीन आपराधिक मामले हैं। प्रतिक्रिया में यह भी कहा गया कि 1,390 मामले जिला और अधीनस्थ अदालतों में 50 से अधिक वर्षों से लंबित हैं। 1,390 मामलों में से 992 दीवानी मामले हैं जबकि 398 आपराधिक मामले हैं। इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (आईसीएमआईएस) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 50 वर्षों से अधिक समय से कोई मामला लंबित नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय 50 से अधिक वर्षों से अपने रिकॉर्ड में लंबित 1,192 दीवानी मामलों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद दिल्ली और मद्रास उच्च न्यायालयों में 133 और 129 मामले हैं।

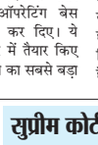

ऑस्ट्रेलिया में तोड़फोड़ की घटनाओं की निंदा

वाशिंगटन। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी चरमपंथ की घटनाओं पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस तरह के घटनाओं और तोड़-फोड़ की कड़ी निंदा करते हैं। हमने खालिस्तान जनमत संग्रह को अपनी अस्वीकृति से अवगत कराया है। हमने वहां पर भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के समक्ष उठाया है। हम इस तरह के घटनाओं और तोड़-फोड़ की कड़ी निंदा करते हैं। हमने खालिस्तान जनमत संग्रह को अपनी अस्वीकृति से अवगत कराया है। हमने वहां पर भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के समक्ष उठाया है। सिंधु जल संधि पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने पाकिस्तान को 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए 25 जनवरी को नोटिस जारी किया है। मुझे पाकिस्तान या विश्व बैंक की ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया की जानकारी नहीं मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करने की खबरों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम यात्रा की घोषणा उचित समय पर करेंगे।

विश्लेषण

लोकसभा चुनाव लड़ेंगे भाजपा के राज्यसभा सांसद!

हरीश गुप्ता

चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि राज्यसभा से आने वाले 18 केंद्रीय मंत्रियों में से कम से कम 10 को मई 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। मोदी की यह भी इच्छा है कि राज्यसभा के 92 भाजपा सांसदों में से कम से कम 25-30 को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। महाराष्ट्र से भाजपा से उभरने वाले प्रमुख नामों में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे और राज्यमंत्री रामदास आठवले (आरपीआई-आठवले) शामिल हैं।

तीसरे कार्यकाल के राज्यसभा सांसद और सदन के नेता पीयूष गोयल, जो कई प्रमुख विभागों को संभाल रहे हैं, भी महाराष्ट्र से हैं। लेकिन वह लोकसभा चुनावों के दौरान पर्दे के पीछे से काम करते हैं और दिल्ली में 2024 के चुनावों के लिए उनकी सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, अन्य राज्यों से संबंधित 8 अन्य केंद्रीय मंत्री जो 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए मैदान में आ सकते हैं, उनमें सर्बानंद सोनोवाल (असम), पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मंडाविया (गुजरात), धर्मेंद्र प्रधान (ओडिशा), ज्योतिरादित्य सिंधिया (मध्य प्रदेश), वी. मुरलीधरन (केरल) शामिल हैं। जिन सांसदों को चुनाव में खड़ा किया जा सकता है उनमें सुशील मोदी (बिहार), सरोज पांडे (छत्तीसगढ़), नीरज शेखर (यूपी) का समावेश है।

कोश्यारी की जगह नहीं ले सकते अमरिंदर सिंह?

राजनीतिक हलकों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जा सकता है। भगत सिंह कोश्यारी द्वारा पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त करने के साथ ही उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है। लेकिन मोदी सत्ता के करीबी माने जाने वाले लोगों का कहना है कि भाजपा कैप्टन को महाराष्ट्र भेजना

पसंद नहीं कर सकती है क्योंकि मई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक भाजपा को उनकी सेवाओं की जरूरत पड़ सकती है।

पंजाब में भाजपा सिर्फ दो सीटें ही जीत सकी (गुरदासपुर) और होशियारपुर) और वह भी अकाली दल के साथ गठबंधन में। अकाली दल के एनडीए से बाहर होने के साथ, भाजपा नेतृत्व पार्टी कैडर को मजबूत करने और अपने आधार का विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। दूसरे, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर, जो पटियाला से कांग्रेस सांसद हैं, मार्च, 2024 में चुनावों की घोषणा होने के बाद भाजपा में जा सकती हैं या अपने बेटे रणिंदर सिंह के पक्ष में अपनी सीट छोड़ सकती हैं। भाजपा पंजाब में 6 से 8 लोकसभा सीटें जीतने और पंजाब में सभी दलों के नेताओं को लुभाने की इच्छुक नजर आती है। हाल ही में, पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।

फड़नवीस का बढ़ता ग्राफ

भाजपा में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस का ग्राफ लगातार चढ़ता जा रहा है। हालांकि वे राजनीतिक मजबूरियों के कारण मुख्यमंत्री पद से चूक गए, लेकिन उनका राजनीतिक दबदबा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक आश्चर्यजनक कदम के रूप में, भाजपा आलाकमान ने उन्हें सर्वशक्तिशाली केंद्रीय चुनाव समिति के लिए नामांकित किया। यह कदम बहुत संकेत पूर्ण है क्योंकि सीईसी में भाजपा शासित राज्यों के किसी भी मुख्यमंत्री को स्थान नहीं दिया गया था। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, देवेंद्र फड़नवीस को दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में आर्थिक प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा गया, जिससे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में बेचैनी पैदा हो गई। अधिक दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा पेश किया गया था। जाहिर है, पार्टी आलाकमान स्पष्ट संकेत देना चाहता है कि राजनीतिक और आर्थिक प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठता ही एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है। दो साल पहले जब भाजपा ने दिल्ली में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कार्यवाही के दौरान राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने के लिए चुना गया था। वे अकेले मुख्यमंत्री थे जो व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल हुए जबकि अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

बिहार में पसरा सन्नाटा

बिहार के तीन घटनाक्रम ध्यान देने योग्य हैं- 1), केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोजपा के सांसद चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया; 2) जनता दल (यू) के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का बैनर उठाया और 3) बिहार भाजपा के नेताओं ने अचानक नीतीश कुमार के खिलाफ चुप्पी साधने के बाद जद (यू) के साथ कोई संबंध नहीं रखने की घोषणा की।

केंद्रीय बजट हर वर्ग के सपनों को पूरा करने वाला बजट : भाजपा

दुर्ग। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला और देश को गति प्रदान करने वाला बजट है। जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि इस बजट के आधार पर भारत ने संकल्पों को लेकर आगे बढ़ेगा। केंद्रीय बजट में निम्न और मध्यम वर्ग के लिए अनेकों सौगातें दी गई है। इस बजट में टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बल दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है जिससे सड़कें, रेल, पोर्ट के क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित होने से भारत के विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे साथ ही देश की बड़ी आबादी को आय के नए अवसर प्राप्त होंगे।

जिला महामंत्री ललित चंद्राकर और सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 66 प्रतिशत की कच्चे मकानों में रहने वाली गरीब जनता के लिए बहुत बड़ा उपहार है। गरीबों के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट में किया गया प्रावधान स्वागत योग्य है। जिला भाजपा उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने कहा करमुक्त आय की सीमा को बढ़ाकर तीन लाख किए जाने और सात लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगने का प्रावधान मध्यमवर्गीय लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात अमृत काल का यह प्रथम बजट देश के विकास की नई गाथा शुरू करेगा।

जिला भाजपा उपाध्यक्ष दिलीप साहू ने कहा कि पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण का लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए करने से देश के किसान वर्ग को सबसे अधिक लाभ पहुंचेगा और किसान फसल उत्पादन के लिए अपने वित्त की आवश्यकता को आसानी से ऋण द्वारा पूरा कर सकेंगे और देश के विकास में अपना और अधिक योगदान दे सकेंगे।

जिला भाजपा उपाध्यक्ष विनायक नातू और नटवर ताम्रकार ने कहा कि मोटे अनाज मिलेट्स को श्रीअन्न के रूप में मान्यता देकर इसके उत्पादन के लिए विशेष कार्य योजना बनने से आदिवासी किसानों को संबल मिलेगा, वहीं मिलेट्स के सेवन और उपयोग से आमजन शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ और मजबूत बनेंगे। जिला उपाध्यक्ष केएस चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2023 से एमएसएमई के क्षेत्र में विकास के लिए जो नई व्यवस्था बनाई गई है उसके कारण लघु और मध्यम क्षेत्र के औद्योगिक इकाइयों को मजबूती मिलेगी, इस सेक्टर के मजबूत होने से देश में रोजगार और नियोजन के नए अवसर पैदा होंगे। जिला भाजपा उपाध्यक्ष अलका बाघमार ने कहा कि केंद्रीय बजट में महिलाओं के लिए लाई गई विशेष बचत योजना से सामान्य गृहिणियों को आर्थिक ताकत मिलेगी। महिला स्व सहायता समूहों के लिए लाई गई नई योजनाएं महिलाओं को समृद्ध बनाने की दिशा में अहम कदम है।

जिला भाजपा मंत्री बोधन यादव, पवन शर्मा, आशीष निमजे ने कहा कि केंद्रीय बजट में पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी और बच्चों व किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है, इससे ग्रामीण अंचल के मेधावी विद्यार्थियों को बेहद मदद मिलेगी और ग्राम स्तर पर लोगों में अध्ययनशीलता बढ़ने से वे अधिक जागरूक होंगे। जिला भाजपा मंत्री रोहित साहू और अमिता बंजारे ने कहा कि देश के युवाओं के लिए 30 नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर के निर्माण से विदेशों में नौकरी करके सपने देखने वाले छात्रों को इंटरनेशनल लेवल का प्रशिक्षण प्राप्त होगा और देश की युवा शक्ति विकास में योगदान देने के लिए लिए और अधिक मजबूत होगी।

जिला भाजपा अध्यक्ष विनोद अरोरा और सह कोषाध्यक्ष नीलेश अग्रवाल ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के सरकार के सिद्धांत ने विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवाओं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति दिव्यांगजन एवं आर्थिक रूप से कमजोर तबके को समावेश करते हुए प्रस्तुत किया गया है। यह बजट देश को समावेशी विकास के पथ पर अग्रसर करेगा।जिला भाजपा कार्यालय मंत्री मनोज सोनी, सह कार्यालय मंत्री मदन वाढ़ई ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही स्वागतयोग्य प्रावधान किए गए हैं, वर्ष 2014 के बाद स्थापित 157 नए मेडिकल कॉलेजों के साथ जोड़कर 157 नर्सिंग कॉलेजों को खोले जाने से स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नर्सिंग स्टाफकी कमी नहीं रहेगी जिसके चलते जनता को अच्छे स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होगी।

जिला भाजपा मीडिया प्रभारी राजा महोबिया और सह मीडिया प्रभारी राकेश दुग्गड़ ने कहा कि बजट में समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने की इच्छा शक्ति है। यह बजट अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिनसे निम्न और मध्यम वर्ग की जनता लाभान्वित होगी।सोशल मीडिया जिला प्रभारी रजनीश श्रीवास्तव और सोशल मीडिया सह प्रभारी नारायण दत्त तिवारी ने कहा केंद्रीय बजट में रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 30 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड का निर्माण देश के आर्थिक व्यावसायिक और औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा।

मुख्यमंत्री बघेल आज भानुप्रतापपुर आएंगे

कांकेर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का 03 फरवरी को भानुप्रतापपुर में प्रवास कार्यक्रम प्रस्तावित है। उक्त प्रवास के अवसर पर सुरक्षा एवं कानून व शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

हेलीपेड स्थल भानुप्रतापपुर में प्रभारी तहसीलदार चारामा श्री यशवंत कुमार की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार सर्किट हाऊस, विश्राम गृह भानुप्रतापपुर में नायब तहसीलदार कोरर एवं भानुप्रतापपुर श्री कुलदीप ठाकुर तथा कार्यक्रम स्थल गोंडवाना भवन भानुप्रतापपुर में देव परिचय बूढ़ादेव राउड़ का लोकार्पण एवं सेवा अर्जी तथा मंच सभा स्थल पर अनुविभागीय अधिकारी भानुप्रतापपुर श्री प्रतीक जैन एवं तहसीलदार भानुप्रतापपुर श्री सुरेन्द्र कुमार उर्वशा की ड्यूटी लगाई गई है। गोंडवाना भवन व्ही.आई.पी. भोजन स्थल पर अनुविभागीय अधिकारी चारामा श्री राकेश कुमार गोलछा तथा तहसीलदार पखांजूर श्री शशि शेखर मिश्रा, व्हीआईपी प्रवेश द्वार सभा स्थल पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी अंतागढ़ श्री के.एस. पैकरा, नागरिक प्रवेश द्वार सभा स्थल में नायब तहसीलदार दुर्गूकोंदल श्री कृष्णा पाटले और पार्किंग स्थल पर तहसीलदार अंतागढ़ श्री राधा कृष्ण बंजारे की ड्यूटी लगाई गई है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री एस. अहिरवार उक्त कार्यक्रम के कानून व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार पर रहेंगे।

अमृतकाल का अंत्योदय बजट: मोहन मण्डावी

नगरी। कांकेर सांसद मोहन मण्डावी ने केंद्रीय बजट को गाँव, गरीब, किसान तथा कमजोर वर्ग वेतनभोगी कर्मचारी के साथ समावेषी विकास का बजट कहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सरकार का यह बजट जो कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को पांचवी बार सदन में पेश किया। इस सम्बंध में कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मण्डावी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट गरीब, जरूरत मंद वर्गों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है इसके अंतगर्त 80 करोड़ लोगों को आने वाले 2 वर्षों तक 2 लाख करोड़ बजट का प्रावधान रखते हुए मुक्त में अनाज देने को प्रस्तावित किया गया है ।

11 करोड़ किसानों को 20 लाख करोड़ का कृषि ऋण फण्ड, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि करने के लिए सहायता देना,1 हजार करोड़ गोबरधन स्कीम के अंतर्गत प्रावधान प्रस्तावित कर किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग देने को प्राथमिकता दिया गया है । इसी तरह किसानों को लोन मे छूट देने की व्यवस्था जारी रहेगी ।

प्रस्तुत बजट में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सांसद ने कहा कि 79 करोड़ प्रधानमत्री आवास योजना को बजट में शामिल कर 66 प्रतिशत फण्ड वृद्धि करना यह भारत सरकार की दूरगामी सोच है । प्रधानमंत्री सुरक्षा योजनांतगर्त 44 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्रदान किया जावेगा । 9.6 करोड़ एल.पी .जी. कनेक्शन उज्जवला योजनांतगर्त प्रदान किया जावेगा ।

महिलाओं का आथिर्क सशक्तिकरण को ध्यान देते हुए महिला सम्मान बचत पत्र

का एलान कर देय ब्याज दर को 7.5 प्रतिषत किया गया । बजट में 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देने का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है।

बजट में 159 नर्सिंग कॉलेज, 150 नये एयरपोर्ट, रेलवे में 2.4 लाख करोड़ का निवेश किया जाना आदि प्रस्तावित है। आदिवासियों के लिए 15 हजार करोड़ को बजट में शामिल किया गया । वेतनभोगी कर्मचारी के लिए इनकम टैक्स में 80 सी के तहत पुराने टैक्स प्रारूप में 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करते हुए आयकर छूट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है । इससे कमर्चारियों को बड़ी राहत मिलेगी ।

इस प्रकार से 2023.24 के भारतीय बजट को कांकेर सांसद ने गाँव, गरीब, किसान, कर्मचारी, मध्यम वर्गीय तथा समावेषी विकास का बजट बताया है।

श्री मण्डावी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण तथा भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए इसे अमृतकाल का अंत्योदय बजट कहते हुए प्रधानमंत्री एवं वित्तमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

सर्व वर्ग और देश को विकास की ओर अग्रसर करने वाला बजट: प्रेमलता नागवंशी

- **पीएम और वित्त मंत्री का जताया आभार**

नगरी। बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के लिये संसद मे बजट पेश किया। उन्होंने देशवासियों को बधाई दी कि कोविड से उबरने के बाद भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने मे कामयाब हो सका।

बजट को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेत्री एवं जिला मंत्री प्रेमलता नागवंशी ने बताया कि देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। देश स्टार्ट अप्स के माध्यम से गुणात्मक रूप से प्रगति कर रहा है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट में सभी वर्गों का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार हेतु 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। रेलवे के लिये पहली बार 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 75000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास के सालाना दस हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। 35 हजार करोड़ ऊर्जा संचार हेतु बजट मे दिया गया। बजट पर केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये बजट में 66त्न की वृद्धि करते हुए 79 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया। 157 नये मेडिकल कॉलेज मे से सभी मे नये नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गयी।एकलव्य आवासीय

विद्यालयों के लिये 39 हजार नये शिक्षकों की नियुक्ति हेतु इस बजट मे घोषणा की गयी। साथ ही महिलाओं के लिये महिला सम्मान बचत योजना शुरू किये जाने की घोषणा की गयी जिसमे 2 लाख तक की बचत पर 7.5त्न ब्याज मिलेगा। राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण योजना की अवधि एक साल और बढ़ाई गयी।वहीं टैक्स को लेकर कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आय कर मे छुट की सीमा 3 लाख की गयी। साथ ही इस बजट की घोषणा के अनुसार वर्ष 2023-24 मे 7 लाख के अंदर तक की संपूर्ण आय पर कोई कर नही लगेगा। वहीं कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कटौती को 50 हजार रू.तक और बढ़ाया गया।अनेक प्रकार के आर्थिक सुधार की नयी योजनाओं की भी घोषणा की गयी।

श्रीमती नागवंशी ने बजट को सर्व वर्ग के लिये हितकारी बताते हुए कहा कि घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रावधान किये गये। कौशल विकास योजना, मनरेगा, पी एम विकास, मिलेट अनाज को प्रोत्साहन सहित बहुत सी योजनाएं इस बजट मे शामिल की गयी। यह बजट सर्व वर्ग के हित और देश को विकास की ओर अग्रसर करने वाला बजट है।जिसके लिये उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करती हूं।

अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने वाला बजट : शांडिल्य

नगरी। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉ. के.एस.शांडिल्य ने केंद्रीय बजट 2023-24 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट में गरीब व मध्यम वर्ग, महिलाओं, युवाओं, किसानों, वरिष्ठ नागरिकों, परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों सहित सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में सात प्राथमिकताएं अपनाई गई है। जो एक दूसरे का सम्पूरण करती है। बजट 2023 - 24 अमृत काल का पहला बजट है। जो हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि के भांति कार्य करती है। बजट समावेशी विकास, अंतिम छोर व अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र पर केंद्रित है।

शांडिल्य ने कहा कि बजट में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत ने विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवाओं, अनसूचित जन जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को कवर करते हुए समावेशी विकास को संभव किया है। बजट में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात कहीं है।

युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्ट अप्स खोल सके इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित करने की बात बजट में कही गई है। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करने 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशलवर्धन के क्षेत्र अन्तर्गत मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सह स्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापति करने की बात बजट में कही गई है। बजट में अगले तीन वर्षों में केन्द्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कार्मिक की नियुक्ति की बात कहीं गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79000 करोड़ रूपए से अधिक कर दी गई है। आयकर सीमा में छूट को बढ़ाकर 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया है। ऐसे ऐतिहासिक बजट के लिए डॉ.शांडिल्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के लिए आभार व्यक्त किया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कुकरेल में निकली कांग्रेस की हाथ जोड़ो पदयात्रा

नगरी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश पर जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन पर जिला प्रभारी अंबिका मरकाम की उपस्थिति में सिहावा विधानसभा क्षेत्र कुकरेल के ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश दुबे की अगुवाई में हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा ग्राम पंचायत चनागांव से प्रारंभ होकर ग्राम पंचायत भोथापारा के आश्रित ग्रामों में हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा संपन्न हुआ उक्त अवसर पर सभी ग्रामों में उपस्थित जनसमुदाय के समस्याओं को सुनकर विधायक डॉ.लक्ष्मी ध्रुव द्वारा त्वरित निदान किया गया। उक्त अवसर पर पीसीसी सचिव शोभीराम नेताम, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रकला नेताम, जिला पंचायत सदस्य मीना बंजारे, जनपद सदस्य सुश्री पुष्पा ध्रुव, छबिलाल सिन्हा जोन अध्यक्ष, गणपत मंडावी, हरिकलाल समुंद, गोवर्धन ध्रुव एवं पदयात्रा में सभी ग्रामों के माताएं युवा साथी एवं बुजुर्ग जन उपस्थित हुए।

मध्यप्रदेश में दिखेगा छग के मल्लखम्ब खिलाड़ियों का दम

नारायणपुर। देश का सर्वश्रेष्ट युथ खेल का महाखुम्भ मे शामिल होने अबुझमाड़ के 10 खिलाड़ी जा रहे है। ये खिलाड़ी 5वां खेलो इंडिया युथ गेम्स 2022 जिसका प्रतिनिधित्व मध्य भारत के मध्यप्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में 6 से 11 फरवरी 2023 तक होने जा रहा है उसमें शामिल होंगे। इनमें 12 खिलाडियो में से बालक एवं बालिका वर्ग का छत्तीसगढ़ टीम के लिए चयन हुआ है, जिसमे 10 जाबांज खिलाडियों का चयन नारायणपुर के अबूझमाड़ मल्लखंब अकादमी से ही हुआ है। इन चयनित खिलाडियों में बालक वर्ग से मानू ध्रुव, मोनू नेताम, श्यामलाल पोटाई, राकेश वरदा, संतोष सोरी, रविन्द्र कुमार और बालिका वर्ग से सरिता पोयाम, दुर्गेश्वरी कुमेटी, संताय पोटाई, जयंती कचलाम, हिमांशी उसेंडी और शिक्षा दिनकर आदि खिलाडियो का चयन हुआ है। साथ ही छत्तीसगढ़ टीम की ओर से मुख्य प्रबंधक के लिए प्रेम चन्द्र शुक्ला और टीम कोच के लिए मनोज प्रसाद एवं श्रीमती पूनम प्रसाद भी इन खिलाडियों के साथ जाएंगे।

दिव्यांगों के लिए मिशन आत्मनिर्भर के तहत शिविर

जगदलपुर। दिव्यांगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए लोहण्डीगुड़ा में मिशन आत्मनिर्भर के तहत आज एक शिविर का आयोजन किया गया, शिविर में 717 दिव्यांगों ने पंजीयन करवाया। लोहण्डीगुड़ा में शिविर का आयोजन करने के पूर्व सभी ग्राम पंचायतों में घर-घर जाकर लोगों से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से दिव्यांगों की पहचान की गई थी। इस अवसर पर कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा कि समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन की यह पहल उन दिव्यांग लोगों तक पहुंचने के लिए है, जो सामान्य तौर पर हम तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने कहा कि आमतौर पर दिव्यांगजन अपनी समस्याओं को रखने के लिए हम तक नहीं पहुच पाते, उनकी समस्याओं के समाधान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। मिशन आत्मनिर्भर के तहत उनकी पहचान कर उन्हें एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है, सभी की समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर किया जा सके। यहां दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, सहायक उपकरण आदि समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है।

छावनी थाने में जब्त वाहनों में लगी आग

भिलाई। छावनी थाना परिसर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब यहां के जब्त वाहनों में अचानक आग लग गई। आग कहां से और कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है लेकिन इस आगजनी के कारण जब्त वाहनों को नुकसान पहुंचा। आग लगने के बाद मौके से ही फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को सूचना दी। मौके पर फायर टेंडर पहुंच गए हैं और आग बुझाने का काम किया जा रहा है। छावनी थाना प्रभारी नवी मोनिका पाण्डेय ने बताया कि थाने के पीछे जब्त वाहनों को रखा गया है। आज दोपहर बाद इसमें अचानक आग लग गई। आग फैलता देख फायरब्रिगेड को बुलाया गया और वे अपना काम कर रहे हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। छावनी थाना प्रभारी ने बताया कि आग लगने का कारण अज्ञात है। जहां पर जब्त वाहन रखे गए हैं वहां इलेक्ट्रिक पोल भी लगा है। संभव है बिजली की चिंगारी से आग लगी हो।

मालगाड़ी के आठ डिब्बे पटरी से उतरे, विशाखापटनम-किरंदुल पैसेंजर रद्द

जगदलपुर। जिले के बचेली से विशाखापट्टनम जा रही मालगाड़ी के आठ डिब्बे गुरुवार सुबह सुबह 6.25 बजे किरंदुल-कोट्टावालसा रेललाइन में शिवलिंगपुरम-बोद्दावारा स्टेशन के बीच पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से आवागमन प्रभावित हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बचेली से लौह अयस्क भरकर मालगाड़ी विशाखापट्टनम जा रही थी, इसी दौरान हादसा हुआ है। हादसा होने की वजह से इस मार्ग में आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। विशाखापटनम-किरंदुल पैसेंजर ट्रेन रद्द कर दी गई है। वहीं किरंदुल से जाने वाली पैसेंजर को कोरापुट से वापस लौटाने का आदेश दिया गया है।

विधायक रंजना की अनुशंसा से देमार-परेवाडीह मार्ग के लिए राशि स्वीकृत

- **खम्हरिया से अंगारा मार्ग के लिए 532 लाख वृहत पुल निर्माण के लिए मिली स्वीकृति**

धमतरी। क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग जिला धमतरी के देमार से परेवाडीह मार्ग में कुरिया नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य व खम्हरिया से अंगारा मार्ग अंगारा नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य जिसको विधायक रंजना डीपेंद्र साहू के द्वारा विधानसभा के पटल पर ध्यानाकर्षण एवं याचिका के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बजट सत्र 2021-22 में उक्त दोनों निर्माण कार्य को शामिल कराई थी, इस मार्ग में पुलिया निर्माण के लिए लगातार क्षेत्रवासियों के द्वारा विधायक के समक्ष अपनी मांग रखी गई थी जिसको विधायक ने विभागीय मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर स्वीकृति प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही, प्रयास स्वरुप जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति के रूप में विधायक रंजना साहू की अनुशंसा से मिली है।

जिसके अंतर्गत देमार से परेवाडीह मार्ग में पुलिया निर्माण एवं पहुंच मार्ग हेतु 873.30 लाख एवं खम्हरिया से अंगारा पहुंच मार्ग के लिए पुलिया निर्माण एवं पहुंच मार्ग हेतु 532.68 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। इससे स्थानीय क्षेत्र वासियों में हर्ष व्याप्त है एवं विधायक रंजना डीपेंद्र साहू का सहृदय धन्यवाद ज्ञापित किए हैं।

विधायक का आभार व्यक्त जागेश्वरी साहू जनपद सदस्य, मुरारी यदु भाजपा मंडल अध्यक्ष, राकेश साहू भाजपा मंडल उपाध्यक्ष, गौकरण साहू भाजपा मंडल उपाध्यक्ष, रवि कुमार ध्रुव सरपंच ग्राम पंचायत खम्हरिया, ओम कुमारी सरपंच ग्राम पंचायत अंगारा, लक्ष्मीनारायण बंजारे सरपंच ग्राम पंचायत डोमा, ललित साहू, सतीश बाबर, भीम साहू, संतोष भीमगज, खेमन साहू, दीनदयाल मिथिलेश, काशीराम ध्रुव, रामकृष्ण साहू , ज्ञानी राम साहू, रामगोपाल ध्रुव, समय दास साहू, अभिमन्यु साहू, भीमसेन साहू, कुंवर सिंह साहू, मंशा राम साहू, भेवेन्द्र साहू, शिवकुमार साहू, सोमनाथ साहू, जनपद सदस्य चंद्रकला बंजारे, देमार सरपंच शीतल मिनपाल, उपसरपंच संजय साहू, पूर्व सरपंच शीत साहू, पूर्व सरपंच बसंत परदेशी मीनपाल, राजू मीनपाल, नारायण साहू, सुरेंद्र चौरे, भूपेंद्र साहू, दुर्गेश सिन्हा, सुरेश साहू, राकेश पटेल, अंगेश्वर साहू, परेवाडीह सरपंच टिकेश्वरी साहू, उपसरपंच सुखराम साहू, नेतप्रकाश जोशी, तेजराम, नंदू राम, राकेश साहू, सुरेश साहू, शीतलेश साहू, भागीरथी साहू , गुहलेद साहू, पुन्नक राम,दुलार सिंह गजपाल, अशोक साहू सहित समस्त क्षेत्रवासियों ने किए हैं।

आँगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की मांगों का जिला भाजपा ने किया समर्थन

कोरबा।आँगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की 6 सूत्रीय मांगों को जायज मान जिला भाजपा कोरबा ने समर्थन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कोरबा को ज्ञापन सौंपा है।

जिला अध्यक्ष डॉ. राजीव सिंह के अगुवाई में जिला भाजपा के पदाधिकारियों 31 जनवरी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर किये जा रहे धरना प्रदर्शन स्थल घंटाघर पहुंच कर उनका समर्थन किये। इस दौरान जिला अध्यक्ष डॉ राजीव सिंह ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगो के मांगों को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण समर्थन करती है और ये मांग पूरी नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी आप लोगो के साथ सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के 6 सूत्रीय मांगो को लेकर 1 फरवरी को कलेक्टर कोरबा संजीव झा से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सौपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पिछले कई दिनों से आँगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। जिसमें मुख्य रूप से नियमितिकरण, रिटायरमेन्ट पेंशन एवं सरकारी वेतन की मांग की गयी है। चूँकि आँगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका आज के समाज में मुख्य भूमिका निभा रहीं है। इनकी मांग जायज है अत: आपसे निवेदन है कि महिला सशक्तिकरण को बल देते हुये उनकी जायज मांगों को यथाशीघ्र पूरा करने की कृपा करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

जेपी नड्डा आज त्रिपुरा में दो रैलियों को संबोधित करेंगे

अगरतला। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा शुक्रवार को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहां दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है। भाजपा ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और पांच सीटें सहयोगी आईपीएफटी के लिए छोड़ी हैं। भाजपा की त्रिपुरा इकाई के मीडिया प्रभारी सुनीत सरकार ने बताया, 'पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा का शुक्रवार को यहां आने का कार्यक्रम है। वह कुमारघाट और अमरपुर में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सुनीत ने बताया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी और बंगाल इकाई के कई अन्य नेता प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी चुनाव प्रचार के लिये यहां जल्द ही आने की संभावना है।

अधीर रंजन ने आम बजट को मित्र काल का बजट बताया

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह जेबकटुआ सरकार बन गई है हमारे जेब से 1000 लेकर हमें 200 देती है। विपक्ष ने वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आम बजट को मित्र काल का बजट करार दिया है। कांग्रेस ने बजट में गरीब, वंचितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं विपक्ष द्वारा बजट को मित्रकाल का बजट बताने पर केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने आजादी के 100 साल तक का रोडमैप बनाया है। उन्होंने कहा, ये जो बोल रहे हैं कि ये अमृतकाल नहीं मित्र काल का बजट है तो उन्हें इसका मतलब नहीं पता और अगर मित्र काल का भी बजट मान लें, तो देश के सभी लोगों को मित्र, दोस्त मानकर बजट लाया गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने संसद के मौजूदा बजट सत्र में उठाये जाने वाले मुद्दों और सरकार को घेरने की रणनीति पर बृहस्पतिवार को चर्चा की।

अजित पवार ने कहा बजट में महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं

पुणे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने कहा कि केंद्रीय बजट ने महाराष्ट्र समेत देश को 'निराश' किया और इसमें मुंबई के लिए कुछ खास नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को 'भ्रामक' और 'चुनावी जुमला' करार देते हुए पवार ने कहा कि इसे लोकसभा चुनाव और नौ राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री पवार ने ट्वीट किया, 'मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए आयकर की छूट सीमा बढ़ाने का ढोंग किया गया है।' उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को पांच हजार अरब डॉलर के आकार तक बढ़ने की घोषण कर केंद्र सरकार ने अपनी अक्षमता को स्वीकार किया है।

नगालैंड की 20 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी घोषित

नई दिल्ली। नगालैंड और मेघालय में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा है कि भाजपा नगालैंड की 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं बाकी की 40 सीटें सहयोगी दल एनडीपीपी को दी गई हैं। नगालैंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तेमजेन इम्ना को अलोंगटकी विधान सभा क्षेत्र से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अन्य नामों की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी 60 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। नलिन कोहली ने कहा है कि मेघालय चुनाव के लिए हमारी टैगलाइन है एम पॉवर मेघालय यानी मोदी पॉवर्ड मेघालय, उन्होंने कहा, जल्द ही यहां भी डबल इंजन की सरकार बनेगी।

सपा का भाजपा पर तंज अहंकार का जल्द होगा अंत!

मुरादाबाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के लिए गुरुवार को मुरादाबाद में प्लेन लैंड करने की अनुमति नहीं मिली। इससे नाराज समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि भाजपा के अहंकार का जल्द अंत होगा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 4 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुरादाबाद में एक समारोह में सम्मिलित होना था लेकिन योगी सरकार प्लेन को लैंड होने की अनुमति नहीं दे रही है। यह बेहद निंदनीय कृत्य है। प्लेन लैंडिग की अनुमति नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने इस पर ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने ट्वीट में लिखा, पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अखिलेश यादव को मुरादाबाद में एक समारोह में सम्मिलित होना था लेकिन योगी सरकार प्लेन को लैंड होने की अनुमति नहीं दे रही है।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर विपक्ष का हंगामा, बाधित रहे दोनों सदन

संसद की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित

नईदिल्ली। बजट पेश किए जाने के दूसरे दिन संसद की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने कारोबारी गौतम अदाणी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जोरदार हंगामा किया। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दिया गया। दो बजे के बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष फिर से जांच की मांग की। इसके बाद संसद के दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

संसद के बजट सत्र में लोकसभा की बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दलों के सदस्य आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। वे अडाणी समूह को लेकर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा कराने की और समूह की कारोबारी प्रक्रियाओं की जांच कराने की मांग कर रहे थे। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से उनके स्थान पर जाने की अपील करते हुए बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया और कहा कि बिना तथ्यों के कोई बात नहीं की जानी चाहिए। इस दौरान अध्यक्ष बिरला ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्य पूनम मदाम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने को कहा, लेकिन हंगामे के बीच वह पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकीं। अध्यक्ष बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा, ''प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।

विधान मंडल अध्यक्षों के (हाल में हुए) सम्मेलन में चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया था कि प्रश्नकाल चलना चाहिए।'' उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा, ''आप बुनियादी सवाल उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। आप सदन की मर्यादा नहीं रखना चाहते। बिना तथ्यों के कोई बात नहीं कीजिए।'' हंगामा नहीं थमने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कुछ ही मिनट बाद अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक अपराह्न दो बजे जब फिर शुरू हुई तो हंगामा जारी रहा। कई सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। शोर-शराबे के बीच पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने

नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की।

उन्होंने कहा, ''राष्ट्रपति महोदया (द्रौपदी मुर्मू) ने दोनों सदनों को संबोधित किया है। अभिभाषण पर लाए जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा महत्वपूर्ण होती है। यह उनका (राष्ट्रपति मुर्मू का) पहला अभिभाषण है। इस पर चर्चा करिये। सदन चर्चा के लिए होता है।'' जोशी ने कहा, ''आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि चर्चा आरंभ करिये।'' पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने भी विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने अपराह्न दो बजकर करीब पांच मिनट परबैठक शुक्रवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर कार्य स्थगन के प्रावधान वाले नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित रही और बैठक को एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे के कुछ ही मिनट बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन में शून्यकाल एवं प्रश्नकाल भी नहीं हो पाया। उच्च सदन में आज पूर्वाह्न 11 बजे कार्यवाही आरंभ होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शांति भूषण के निधन का उल्लेख किया। उनके योगदान की सराहना करते हुए धनखड़ ने कहा कि शांति भूषण उच्च सदन के पूर्व सदस्य थे। इसके बाद सदस्यों ने उनके सम्मान में कुछ देर मौन रखा। धनखड़ ने इसके बाद सदन को बताया कि उन्हें विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी (आप) के संजय सिंह, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के तिरुची शिवा सहित कुल नौ सदस्यों की ओर से नियम 267 के तहत नोटिस मिले हैं। उन्होंने पूर्व की अपनी व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि इनमें से कोई भी नोटिस स्वीकार किए जाने की अनिवार्यताओं को पूरा नहीं करता है, लिहाजा उन्होंने इन्हें अस्वीकार कर दिया।

उनके ऐसा कहते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। धनखड़ ने सदस्यों से सदन में शांति और व्यवस्था बहाल करने का अनुरोध किया लेकिन अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने सदन की कार्यवाही 11 बजकर सात मिनट पर दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर दो बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति धनखड़ ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने और उस पर चर्चा कराने के लिए कहा। किंतु विपक्षी सदस्यों ने नियम 267 के तहत सदन में चर्चा कराने की मांग शुरू कर दी। सदन में हंगामा शुरू होने के कारण सभापति ने दोपहर दो बजकर तीन मिनट पर बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय के अनुसार, कांग्रेस नेता खरगे ने नियम 267 के तहत बाजार मूल्य खोने वाली कंपनियों में एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निवेश के मुद्दे पर चर्चा का नोटिस दिया था।

शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने एलआईसी, एसबीआई आदि की होल्डिंग्स के ओवरएक्सपोजर की रिपोर्ट की गई घटनाओं के आलोक में तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा कराने का नोटिस दिया था। विजय चौक पर विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में खरगे ने संवाददाताओं से कहा, ''हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार क्यों दबाव बनाकर ऐसी कंपनियों को कर्ज दिलवा रही है?'' उन्होंने कहा, ''लोगों के हित में ध्यान रखते हुए, एलआईसी, एसबीआई के निवेश को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि या तो जेपीसी गठित करके इसकी जांच हो या उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी जांच हो।'' कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खरगे ने कहा, ''जांच होने पर प्रतिदिन रिपोर्ट जनता के समक्ष रखी जाए ताकि पारदर्शिता रहे और लोगों को विश्वास रहे कि उनका पैसा बचा है।

अडाणी इंटरप्राइजेज मामले में विपक्ष की मांग

सुप्रीम कोर्ट या संसदीय समिति करे आरोपों की जांच, संसद में हंगामा

नयी दिल्ली। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने बृहस्पतिवार को अडाणी एंटरप्राइजेज मामले पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग की और यह आग्रह भी किया कि इस प्रकरण की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित की जाए या फिर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में इसकी जांच हो। अडाणी सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की बैठक दोपहर दो बजे तक स्थगित होने के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संवाददाताओं से कहा, ''हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार क्यों दबाव बनाकर ऐसी कंपनियों को कर्ज दिलवा रही है?'' उन्होंने कहा, ''लोगों के हितों और एलआईसी, एसबीआई के निवेश को ध्यान में रखते हुए, हम चर्चा की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जेपीसी गठित करके इसकी जांच हो या उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी जांच हो।''

कई विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में खरगे ने कहा, ''जांच होने पर प्रतिदिन रिपोर्ट जनता के समक्ष रखी जाए ताकि पारदर्शिता रहे और लोगों को विश्वास रहे कि उनका पैसा बचा है।'' इससे पहले, इस विषय पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद के दोनों की कार्यवाही बाधित हुई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ''संसद के दोनों सदनों को आज दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि सरकार एलआईसी, एसबीआई और अन्य सार्वजनिक संस्थानों द्वारा दबाव में किए गए निवेश की जांच के लिए संयुक्त विपक्ष की मांग पर सहमत नहीं हुई।'' उन्होंने दावा किया कि ऐसे निवेश के मूल्यों में कमी के कारण आज करोड़ों भारतीयों की बचत खतरे में है। इससे पहले, बृहस्पतिवार सुबह खरगे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय एवं डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, द्रमुक की कनिमोई, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के संजय राउत और कुछ अन्य दलों के नेता मौजूद थे।

विपक्षी दलों ने फैसला किया है कि वे दोनों सदनों में अडाणी एंटरप्राइजेज से जुड़ा मुद्दा उठाएंगे और इस पर चर्चा की मांग करेंगे। खरगे ने अडाणी एंटरप्राइजेज का प्रत्यक्ष उल्लेख किए बिना राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्यस्थगन का नोटिस दिया था। नोटिस में मांग की गई थी कि बाजार में पूंजी गंवाती कंपनियों में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निवेश के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी कार्यस्थगन का नोटिस देकर अडाणी एंटरप्राइजेज के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि अडाणी प्रकरण पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन होना चाहिए। गौरतलब है कि अडाणी एंटरप्राइजेज ने बुधवार को अपने 20 हजार करोड़ रुपये के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की। हालांकि, कंपनी के एफपीओ को मंगलवार को पूर्ण अभिदान मिल गया था। समझा जाता है कि अडाणी एंटरप्राइजेज ने यह कदम अमेरिका की शॉर्टसेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उठाया है। इस कारोबारी समूह ने रिपोर्ट को निराधार बताया था।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत-आस्ट्रेलिया के बीच 9 से बॉर्डर-गावस्कर सीरीज

नईदिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 9 फरवरी से नागपुर में 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से यह टेस्ट सीरीज काफी महत्वपूर्ण होगा। वहीं अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा देती है तो टेस्ट रैंकिंग में टीम पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। इसी के साथ टीम इंडिया सभी फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बन सकती है।

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फिलहाल भारतीय टीम 115 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम 126 अंकों के साथ पहले पायदान पर काबिज है। ऐसे में टीम इंडिया के पास टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 1 का स्थान हासिल करने का शानदार मौका है। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को इस टेस्ट सीरीज में दो 2 मुकाबले जीतने जरूरी होंगे।

वनडे और टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम पहले ही नंबर 1 स्थान पर काबिज है। वनडे में टीम इंडिया 114 अंकों के साथ पहले स्थान पर काबिज है। वहीं श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के साथ भारतीय टीम ने टी20 रैंकिंग में नंबर 1 के स्थान पर अपनी स्थिति को और भी मजबूत किया है। टीम इंडिया इस समय टी20 प्रारूप में 267 अंक के साथ पहले पायदान पर स्थित है।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट- 9 से 13 फरवरी, नागपुर
दूसरा टेस्ट- 17 से 21 फरवरी, दिल्ली
तीसरा टेस्ट- 1 से 5 मार्च, धर्मशाला
चौथा टेस्ट- 9 से 13 मार्च, अहमदाबाद।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 224 अंक चढ़ा निफ्टी लाल निशान पर बंद

नई दिल्ली। गुरुवार के कारोबारी सेशन में उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 224.16 अंकों की बढ़त के साथ 59,932.24 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 5.90 अंकों की गिरावट के साथ 17610.40 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 156 अंकों की मजबूती के साथ 40669 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। गुरुवार को बाजार में निचले स्तरों पर खरीदारी दिखी। अदाणी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के शेयरों में बढ़त दिखी। बजट 2023-24 में सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने के बावजूद आईटीसी के शेयरों में करीब 5 फीसदी की तेजी दिखी। गुरुवार को यह 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर करीब 27 फीसदी की गिरावट के साथ 1565 रुपये के स्तर पर बंद हुए। पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में यह 1495 रुपये तक फिसला।

अदाणी समूह के कर्ज-निवेश का बैंक ब्योरा दें : आरबीआई

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों से अदाणी समूह में उनके एक्पोजर की जानकारी मांगी है। सरकार और बैंकिंग क्षेत्र के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि केंद्रीय बैंक ने विभिन्न घरेलू बैंकों से अदाणी समूह में उनके निवेश और ऋणों के के बारे में जानकारी देने को कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कदम वर्तमान में जारी अदाणी समूह के शेयरों में उठा-पटक के बाद लिया है। बीते दिन ही अदाणी समूह ने अपना एफपीओ वापस ले लिया था। गुरुवार की सुबह शेयर बाजार खुलने के बाद अदाणी समूह के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक विभिन्न बैंकों से अदाणी समूह में उनकी ओर से दिए गए ऋण व निवेश की जानकारी लेकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अदाणी के शेयरों में ताजा उठा-पटक के माहौल के बीच बैंकों की वित्तीय स्थिति ठीक बनी रहे।

अडानी ग्रुप का बाजार पूंजीकरण 100 बिलियन डॉलर घटा

नयी दिल्ली। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी समूह की कंपनियों पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद इसकी कंपनियों के शेयर लगातार टूटने से उसके बाजार पूंजीकरण में 100 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। वहीं अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 15 प्रतिशत टूट गया। इसके साथ ही समूह की ज्यादातर कंपनियों के शेयर में जबरदस्त गिरावट देखा गया। बीएसई पर कंपनी का शेयर गुरुवार 15 प्रतिशत टूटकर 1,809.40 रुपये पर आ गया। समूह की अन्य कंपनियों का प्रदर्शन भी लगातार छठे दिन कमजोर रहा। अडानी पोर्ट्स के शेयर में 14 फीसदी की गिरावट आई, अडानी ट्रांसमिशन में 10 फीसदी, अडानी ग्रीन एनर्जी में 10 फीसदी, अडानी टोटल गैस में 10 फीसदी, अडानी विल्मर में पांच फीसदी, एनडीटीवी में 4.99 फीसदी और अडानी पॉवर में 4.98 फीसदी की गिरावट आई।

ह्यूंदै ने अपडेट की एसयूवी रेंज, जोड़े नए फीचर्स

नई दिल्ली। साउथ कोरियाई कार कंपनी ह्यूंदै की ओर से साल 2023 में पूरी एसयूवी रेंज में कई खास बदलाव किए गए हैं। कंपनी ने साल 2023 के लिए अपनी सभी एसयूवी को अपडेट कर दिया है। अब बाजार में वेन्यू, क्रेटा और अल्काजार जैसी एसयूवी में पहले के मुकाबले ज्यादा फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे और कंपनी ने इंजन में भी कई बदलाव किए हैं जिससे यह भविष्य में और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ ही फ्लेक्स फ्यूल पर भी चलाए जा सकेंगे। ह्यूंदै मोटर इंडिया के सीओओ तरूण गर्ग ने कहा कि एक कस्टमर सेंटिंग ऑर्गनाइजेशन के तौर पर हमने हमेशा अपने कस्टमर्स के लिए एग्जेम्प्लरी मोबिलिटी एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है। हुंडई की पूरी एसयूवी रेंज पर हमारे MY'23 अपडेट की शुरुआत के साथ, हमने और ज्यादा बेहतर पैकेज देने की कोशिश की है जिसमें सेफ्टी, सुविधा और परफॉर्मेंस शामिल है।

कई वर्षों तक खुशहाली लाएगा मोदी सरकार का यह बजट

कुमार मंगलम बिड़ला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में अमृत काल यानी इंडियाञ्च100 का ब्लूप्रिंट पेश किया है। अमृत काल के इस विजन में एक ओर आधुनिक तकनीक, ग्रीन ग्रोथ (अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा), डिजिटल और फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न सिटीज और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को रखा गया है तो दूसरी ओर हैंडिक्राफ्ट्स और मिलेट्स (मोटे अनाज) में देश को मजबूत बनाने के उपाय किए गए हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें देश पारंपरिक रूप से अच्छा करता आया है। बजट में जो ग्रोथ का रास्ता दिया गया है, उसमें भारत की क्षेत्रीयता और डेमोग्राफिक डायवर्सिटी को भी शामिल किया गया है। बजट में युवा शक्ति का लाभ उठाने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की भी बात है। इसमें यह भी कोशिश की गई है कि देश की तरक्की का लाभ सबको मिले।

पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर फोकस करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धीमी पड़ती ग्लोबल ग्रोथ के बीच ना सिर्फ सुस्त पड़ती डिमांड को बढ़ाने की पहल की है बल्कि वह रास्ता भी दिखाया है, जिससे भारत विकसित अर्थव्यवस्था बनेगा। बजट प्रस्तावों से पता चलता है कि सरकार का ध्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट पर बना रहेगा, जिससे निजी क्षेत्र की ओर से निवेश बढ़ने का माहौल बनेगा।

सरकार ने अगले वित्त वर्ष में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर 13.7 लाख करोड़ का होगा। इससे खपत बढ़ने और निजी क्षेत्र की ओर से निवेश में बढ़ोतरी की उम्मीद है। सरकार की ओर से इतने बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाने से रोजगार के और मौके बनेंगे।

ध्यान रहे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में

जबरदस्त बढ़ोतरी के बावजूद राजकोषीय घाटे और ब्याज दरों को कम रखने में मदद मिलेगी क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सिर्फ 1.2 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। अभी ब्याज दरें ऊंचे स्तर पर हैं, इसलिए यह बहुत ही अहम बात है। इससे इकॉनमी को कई स्तरों पर लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, इन्फ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र के लिए निवेश के मौकों के साथ MSME को भी राहत दी गई है। इसके साथ कंपनियों के लिए कंप्लायंस की लागत कम करने के कदम भी उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने 'LiFE' यानी लाइफस्टाइल फॉर एन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की खातिर जीवनशैली का विजन दिया है। इससे ग्रीन ग्रोथ के अजेंडा को बढ़ावा मिलेगा। इसी के तहत सरकार ने नैशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 19,700 करोड़ रुपये देने की बात कही है। इससे पेट्रोल-डीजल जैसे ईंधन पर निर्भरता घटेगी और कच्चे तेल के आयात में भी कमी आने की उम्मीद है। ग्रीन एनर्जी को अपनाने और नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य हासिल करने के लिए बजट में और 35,000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है।

बजट में इन्क्लूसिव डिवेलपमेंट यानी समावेशी विकास को प्राथमिकता में काफी ऊपर रखा गया है। इसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक और क्षेत्रीय रूप से पिछड़े इलाकों पर ध्यान दिया गया है। भविष्य के तकनीकी बदलावों को ध्यान में रखते हुए और भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति बनाने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के लिए तीन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात कही गई है। इसके लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों और बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी की जाएगी। यह भी कहा गया है कि स्टार्टअप्स और एकेडमिक जगत में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नैशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी के तहत उन्हें डेटा तक पहुंच दी जाएगी।

इस बजट में लंबी और छोटी अवधि के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सही संतुलन बनाया गया है। वहीं, ग्रोथ के साथ उसका फायदा सब तक पहुंचाने की कोशिश दिखती है। निवेश और खपत को बढ़ावा देने का भी प्रयास दिखता है। इस बजट से आर्थिक विकास दर तेज तो होगी ही, बल्कि ना सिर्फ वित्त वर्ष 2023 बल्कि आने वाले वर्षों में भी समृद्धि आएगी।

रामचरितमानस विवाद को दूसरा मंडल कमंडल बनाना चाहते हैं अखिलेश

अजय कुमार

समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर एक विवादित टिप्पणी के बाद राजनीति के गलियारों में यह बात बड़े जोरों शोरों से फैलाई जा रही थी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने बड़बोले नेता स्वामी के बयान से काफी नाराज हैं और उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकते हैं। यह खबर बाकायदा मीडिया में भी खूब चली थी, यहां तक कि सपा की एक नेत्री ने तो स्वामी को बसपा का एजेंट बता दिया था। कुछ समय पूर्व समाजवादी पार्टी में लौट कर आए शिवपाल यादव ने रामचरितमानस पर स्वामी के बयान को उनकी निजी राय बताते हुए पार्टी की तरफ से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन दस दिन भी नहीं बीते होंगे कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस विवादित शख्स स्वामी प्रसाद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा कर यह साबित कर दिया है कि उनके लिए राजनीति से इतर कुछ भी नहीं है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए तो पहले अपने पिता-चाचा का अपमान करने वाले अखिलेश यादव को उनकी अपनी ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी में कुछ बुरा नहीं लगा होगा अन्यथा वह स्वामी प्रसाद मौर्य को इतनी जल्दी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नहीं बना देते।

वैसे यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समाजवादी पार्टी का उत्थान ही भगवान राम का अपमान करने से हुआ है। पिता मुलायम सिंह यादव राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे तो बेटा अखिलेश यादव उन लोगों की पैरोकारी कर रहा है जो रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। आज जिस तरह से हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के खिलाफ खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, वैसे ही कभी आजम खान, सपा सांसद शफीक उर-रहमान बर्क और मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन जैसे तमाम नेता बोलते रहते हैं। हिंदुओं को बांट और लड़ा कर ही यह पार्टी सत्ता में आती है और तुष्टीकरण की सियासत करती है। ईद के दौरान इफ्तार के समय मुस्लिम लबादा ओढ़कर वहां पहुंच जाना समाजवादी नेताओं की दिनचर्या बन जाती है। पिछले करीब एक दशक, जबसे मोदी ने हिंदुओं को एकजुट किया है, तबसे हिंदुओं को बांटने में यह पार्टी सफल नहीं हो पाई, तो सत्ता भी इसके हाथों से खिसक गई। इस पार्टी के नेता आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेते हैं, बलात्कार की घटनाओं पर कहा जाता है कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो उसे फांसी थोड़ी दे दी जाएगी। सत्ता में रहकर कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए पैसा बांटते हैं। हिंदू कन्याओं को छोड़कर मुस्लिम लड़कियों को वजीफा देते हैं। दंगों के समय दंगाइयों का धर्म देखकर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सत्ता में रहते थाने से अपराधियों को छुड़ाने जाने का इनका इतिहास रहा है। यह वही पार्टी है जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, डीपी यादव जैसे बाहुबलियों और यहाँ तक कि डकैतों के परिवार वालों तक को चुनाव लड़ा चुकी है। बहरहाल, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें पदोन्नति दिए जाने से यह साफ है कि जिन लोगों को लगता था कि अखिलेश यादव साफ-सुथरी राजनीति करते हैं, उनको अपना यह भ्रम दूर कर लेना चाहिए।

बजट से आर्थिक बुनियाद को मजबूती

ललित गर्ग

अमृत काल का पहला बजट अनेक दृष्टियों एवं दिशाओं से महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक है, क्योंकि इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सात फोकस क्षेत्रों की बात की, जिन्हें उन्होंने सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए 'सप्तऋषि' कहा। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज, इन सात ऋषियों को सप्तर्षि कहा जाता है, जो सृष्टि का संतुलन बनाने में अपनी योगदान देते हैं। भारत आर्थिक विकास एवं संतुलन में इन ऋषियों को आधार बनाने की बात एक मौलिक सोच एवं दिशा है। दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित करने एवं सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिये इस सप्तर्षि रूपी बजट में सात फोकस क्षेत्रों में समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्रों पर बल दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल और सामाजिक विकास की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाता है। यह बजट देश को न केवल विकसित देशों में बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर बनाये रखने में सहायक बनेगा, विकास दर को 7 प्रतिशत बनाये रखेगा एवं अगले वर्ष भारत अधिक तीव्र गति से विकास कर सकेगा। निश्चित ही सप्तर्षि से उपमित यह बजट आगामी आजादी की शताब्दी तक ले जाने वाले 25 वर्षों में भारत की आर्थिक बुनियाद को मजबूती देने का माध्यम बनेगा।

सशक्त एवं विकसित भारत निर्मित करने, उसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दृष्टि से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, न कि लोकलुभावन योजनाओं के जरिये प्रशंसा पाने अथवा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। राजनीतिक हितों से ज्यादा देशहित को सामने रखने की यह पहल अनूठी है, प्रेरक है। अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जो इस बजट से पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। इस बजट में मध्यम वर्ग को लम्बे अन्तराल के बाद 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई करने वालों को बड़ी राहत दी है। इन लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब की संख्या भी घटाकर

5 कर दी गई है। बजट में महिला बचत सम्मान योजना लॉन्च करके महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने एवं बचत को प्रोत्साहित करने का भी प्रयत्न किया गया है। इसके तहत 7.5 फीसदी का सालाना ब्याज मिलेगा। किसानों के लिए श्री अन्न योजना लॉन्च की गयी है, इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा मिलेट्स संस्थान की भी हैदराबाद में स्थापना की जाएगी। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे भारत की रेल को मजबूती एवं नयी उन्नत शक्ल मिलेगी। वहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10 हजार करोड़ रुपये की रकम जारी की जाएगी। बीते कुछ सालों में नरेन्द्र मोदी ने इकॉनमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़ा करने का मौका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे।

740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। घरेलू और अतंरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए देश में 50 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। उनका विकास प्रतिस्पर्धी आधार पर किया जाएगा। मोदी सरकार ने गरीबों की भी बल्ले-बल्ले करवा दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार का आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा भी सराहनीय है, वहीं, कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता देने की दृष्टि से भी बजट में प्रावधान किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। आदिवासी समुदाय के उन्नयन के लिये भी बजट में ध्यान दिया गया है। यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था के उन्नयन एवं उम्मीदों को आकार देने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण एवं संतुलित विकास सुनिश्चित होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था का जो नक्शा सामने आया है वह इस मायने में उम्मीद की छांव देने वाला है। इस बजट में शहर एवं गांवों के संतुलित विकास पर बल दिया है, जो इस बजट की विशेषता है।

भारत की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से यह बजट कारगर साबित होगा, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, रोजगार के नये अवसर सामने आयेंगे, उत्पाद एवं विकास को तीव्र गति मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक क्षेत्र में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट के माध्यम से देश को स्थिरता की तरफ ले जाते दिखाई पड़ रहे हैं। बजट हर वर्ष आता है। अनेक विचारधाराओं वाले वित्तमंत्रियों ने विगत में कई बजट प्रस्तुत किए। पर हर बजट लोगों की मुसीबतें बढ़ाकर ही जाता रहा है। लेकिन इस बार बजट ने बिगड़ी अर्थव्यवस्था में नयी परम्परा के साथ राहत की सांसें दी है तो नया भारत- सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प भी व्यक्त किया है। इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रेलों का विकास, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ किसानों, गांवों और गरीबों को ज्यादा तवज्जो दी गयी है। सच्चाई यही है कि जब तक जमीनी विकास नहीं होगा, तब तक आर्थिक विकास की गति सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। इस बार के बजट से हर किसी ने काफी उम्मीदें लगा रखी थीं और उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है। विशेषत: नौकरीपेशा लोगों ने राहत की सांस ली है। इस बार आम बजट को लेकर उत्सुकता इसलिए और अधिक थी, क्योंकि यह बजट पड़ोसी देशों के लगातार हो रहे हमलों, निस्तेज हुए व्यापार, रोजगार, उद्यम की स्थितियों के बीच प्रस्तुत हुआ है। संभवत: इस बजट को नया भारत निर्मित करने की दिशा में लोक-कल्याणकारी बजट कह सकते हैं।

यह बजट वित्तीय अनुशासन स्थापित करने की दिशाओं को भी उद्घाटित करता है। आम बजट न केवल आम आदमी के सपने को साकार करने, आमजन की आकांक्षाओं को आकार देने और देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है बल्कि यह देश को समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण एवं दूरगामी सोच से जुड़ा कदम है। बजट के सभी प्रावधानों एवं प्रस्तावों में जहां 'हर हाथ को काम' का संकल्प साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से उजागर हो रहा है। आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत यह बजट निश्चित ही अमृत बजट है। जिसमें भारत के आगामी 25 वर्षों के समग्र एवं बहुमुखी विकास को ध्यान में रखा गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आशा के अनुरूप ही बजट का फोकस किसानों, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, रोजगार, युवाओं की अपेक्षाओं, विकास और ग्रामीण क्षेत्र पर रखा है। अपने ढांचे में यह पूरे देश का बजट है, एक आदर्श बजट है। इसका ज्यादा जोर सामाजिक विकास पर है। मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस मोटे अनाज को प्रोत्साहित करते हुए किसानों के हितों को ही साधने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर है। अक्सर बजट में राजनीति, वोटनीति तथा अपनी व अपनी सरकार की छवि-वृद्धि करने के प्रयास ही अधिक दिखाई देते हैं लेकिन इस बार का बजट इस वर्ष नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बावजूद राजनीति प्रेरित नहीं है। इस बजट में जो नयी दिशाएं उद्घाटित हुई हैं और संतुलित विकास, भ्रष्टाचार उन्मूलन, वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था का जो संकेत दिया गया है, सरकार को इन क्षेत्रों में अनुकूल नतीजे हासिल करने पर खासी मेहनत करनी होगी।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

पैङ्गलोपनिषद् (भाग-3)

गतांक से आगे...

सत्त्व समष्टि से उसने पाँचों इन्द्रियों के पालक देवताओं का सृजन किया और उन्हें ब्रह्माण्डों में स्थापित कर दिया। उसकी (विष्णु रूप ब्रह्म की) आज्ञा से वे सभी (देवगण) ब्रह्माण्डों में स्थित होकर निवास करने लगे। उस (ब्रह्म) की आज्ञा से अहंकार समन्वित विराट्, स्थूल जगत् का संरक्षण करने लगा। हिरण्यगर्भ उसकी आज्ञा से सूक्ष्म तत्त्व का पालन करने लगा।

ब्रह्माण्ड में स्थित वे देवगण उस (ब्रह्म) के बिना न तो स्पन्दन कर सके और न ही कोई चेष्टा कर सके। तब उस (ब्रह्म) ने उन्हें चैतन्य करने की इच्छा की। वह ब्रह्माण्ड, ब्रह्मरन्ध्र और समस्त व्यष्टि के मस्तक को विदीर्ण करके उसी में प्रवेश कर गया, तब वे जड़ता सम्पन्न होते हुए भी चेतन की तरह अपने- अपने कर्म में प्रवृत्त हो गये। सर्वज्ञ ईश्वर मायायुक्त होकर व्यष्टि रूप शरीर में प्रविष्ट हो गया और मोह के कारण जीवत्व (जीव भाव) को प्राप्त हो गया। तीन प्रकार के (स्थूल, सूक्ष्म और कारण) शरीरों से तादात्म्य स्थापित करके कर्तापन और भोक्तापन का अनुभव करने लगा। जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्च्छा आदि स्थितियों वाला होकर मरण धर्म को प्राप्त करके घटीयंत्र (रहट) के समान उद्विग्न (चंचल) होकर तथा कुम्भकार के चक्र के समान उत्पन्न और मृत होता हुआ जगत् में परिभ्रमण करने लगा।

पैङ्गल ऋषि ने पुन: याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया कि समस्त लोकों की सृष्टि, उनका पालन और अन्त करने वाला विभु ईश्वर किस तरह जीवभाव को प्राप्त होता है ?

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के उद्भवपूर्वक जीव और ईश्वर के स्वरूप की विवेचना करता हूँ, उसे सावधान और एकाग्रचित्त होकर सुनो। ईश्वर ने पंचीकृत महाभूतों के अंशों को लेकर व्यष्टि और समष्टि के स्थूल शरीरों का क्रमश: सृजन किया है। कपाल, चर्म, आँतें, अस्थि, मांस और नख (नाखून) ये पृथिवी तत्त्व के अंश से निर्मित हैं। रक्त, मूत्र, लाल (लार) और पसीना आदि जल तत्त्व के अंश से बने हैं। क्षुधा, तृष्णा (प्यास), उष्णता (गर्मी), मोह, मैथुन आदि अग्नि तत्त्व के अंश से बने हैं। चलना, उठना, बैठना, श्वास आदि वायु तत्त्व के अंश से हैं। काम, क्रोध आदि आकाश तत्त्व के अंश से हैं। इस प्रकार इन सबके संघात (समुच्चय) स्वरूप एवं संचित कर्मों से निर्मित त्वचा आदि से युक्त बाल्यावस्था आदि के भाव वाला अनेक दोषों का आश्रय रूप यह स्थूल शरीर होता है।

क्रमश:

संगीत सीखने जब घर से भाग निकले थे भीमसेन

पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने के महत्त्वपूर्ण शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने 19 साल की उम्र से गायन शुरू किया था और वे सात दशकों तक शास्त्रीय गायन करते रहे। भीमसेन जोशी ने कर्नाटक को गौरवान्वित किया है। भारतीय संगीत के क्षेत्र में इससे पहले एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, पंडित रविशंकर और लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी योग्यता का आधार उनकी महान् संगीत साधना है। देश-विदेश में लोकप्रिय हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान् गायकों में उनकी गिनती होती थी। अपने एकल गायन से हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए युग का सूत्रपात करने वाले पंडित भीमसेन जोशी कला और संस्कृति की दुनिया के छठे व्यक्ति थे, जिन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान %भारत रत?त% से सम्मानित किया गया था। %किराना घराने% के भीमसेन गुरुराज जोशी ने गायकी के अपने विभिन्?न तरीकों से एक अद्भुत गायन की रचना की। देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिलने के बारे में जब उनके पुत्र श्रीनिवास जोशी ने उन्हें बताया था तो भीमसेन जोशी ने पुणे में कहा था कि- मैं उन सभी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों की

तरफ से इस सम्मान को स्वीकार करता हूं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी संगीत को समर्पित कर दी।

पंडित भीमसेन जोशी कर्नाटक के गड़ग में 4 फ़रवरी, 1922 ई. को भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था। उस घटना को याद कर उन्होंने विनोद में कहा- ऐसा करके उन्होंने परिवार की परम्परा ही निभाई थी। मंज़िल का पता नहीं था। रेल में बिना टिकट बैठ गये और बीजापुर तक का सफर किया। टी.टी. को राग भैरव में %जागो मोहन प्यारे% और %कौन-कौन गुन गावे% सुनाकर मुग्ध कर दिया। साथ के यात्रियों पर भी उनके गायन का जादू चल निकला। सहयात्रियों ने रास्ते में खिलाया-पिलाया। एक संगीत प्रेमी ने सलाह दी, 'संगीत सीखना हो तो ग्वालियर जाओ।'

रेल गाड़ियाँ बदलते और रेल कर्मियों से बचते-बचाते भीमसेन आख़िर ग्वालियर पहुँच गये। वहाँ के माधव संगीत विद्यालय में प्रवेश ले लिया। किंतु भीमसेन को किसी कक्षा की नहीं, एक गुरु की ज़रूरत थी। भीमसेन तीन साल तक गुरु की खोज में भटकते रहे। फिर उन्हें करवल्लभ संगीत सम्मेलन में विनायकराव पटवर्धन मिले। विनायकराव को आश्चर्य हुआ कि सवाई गन्धर्व उसके घर के बहुत पास रहते हैं। सवाई गन्धर्व ने भीमसेन को सुनकर कहा, मैं इसे सिखाऊँगा यदि यह अब तक का सीखा हुआ सब भुला सके। डेढ़ साल तक उन्होंने भीमसेन को कुछ नहीं सिखाया। एक बार भीमसेन के पिता उनकी प्रगति का हाल जानने आए, उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह अपने गुरु के घर के लिए पानी से भरे बड़े-बड़े घड़े ढो रहे हैं। भीमसेन ने अपने पिता से कहा- मैं यहाँ खुश हूँ। आप चिन्ता न करें।

वर्ष 1941 में भीमसेन जोशी ने 19 वर्ष की उम्र में मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी। उनका पहला एल्बम 20 वर्ष की आयु में निकला, जिसमें कन्नड़ और हिन्दी में कुछ धार्मिक गीत थे।

यात्रा से नहीं, भारतीय विचार स्वीकारने से बनेगी बात

अनिल जावलेकर

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को कश्मीर पहुंचकर समाप्त हो गयी। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा श्रीनगर तक चली। इस यात्रा के पीछे राहुल गांधी की चुनावी पहचान बनाने का प्रयास था इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन यात्रा जैसे प्रतीकात्मक संकेतों से क्या उपयुक्त पहचान बन पाएगी यह सोचने और देखने की बात होगी। इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान जिन लोगों के साथ फोटो खिंचवाई उससे उन लोगों को पहचान मिली। वैसे यह यात्रा ऐसे ही कांग्रेसियों और उनके साथियों को जोड़ने के लिए थी ऐसा कहना ही ठीक होगा। यह सही है कि भारतीयों को समझने के लिए यात्रा का उपयोग होता रहा है लेकिन विचार में स्पष्टता के लिए भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझना ज्यादा जरूरी है। इस संदर्भ में राहुल गांधी को अपने विचार में स्पष्टता लाने में मदद मिली है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

निश्चित तौर पर नेहरू परिवार के सदस्य होने के नाते ही राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मिला है और यही उनकी अभी तक की पहचान है। बाकी उनकी कोई विचारधारा स्पष्ट नहीं हुई है। वे अपने आप को जैसे अभिव्यक्त करते हैं उससे तो यही लगता है कि कोई पहले बता देता है और वो बस बोल देते हैं। इससे विचारों में गड़बड़ी जाहिर होती है। शायद इसी वजह से उनकी नेतृत्व वाली पहचान नहीं बन पाई है। यह कहने की आवशकता नहीं है कि उनका अब तक का व्यवहार और वैचारिक प्रदर्शन देश के सामने कोई ठोस राजनीतिक पर्याय नहीं रख पाया है। वैसे राहुल गांधी अभी भी अपने परदादा-दादी की पार्टी को एक वारिस की तरह चला

रहे हैं और उनके ही पुराने लोग और पुराने दांवपेच पर भरोसा रखे हुए हैं। लेकिन इससे अपनी खुद की राजनीतिक दृष्टि और देश की समस्या के प्रति अपना विचार न तो स्पष्ट होता है, न ही इससे कोई अपनी पहचान बन पाती है। यही कारण है जनता तो दूर की बात, विपक्षी दल भी उनके नेतृत्व में विश्वास नहीं कर रहे हैं।

राहुल गांधी को पहली बात यह समझना जरूरी है कि देश के भीतरी और बाहरी दुश्मनों से दोस्ती और उनके प्रभाव में रहने से उनकी अपनी पहचान खराब हो रही है। यह सही है कांग्रेस की स्थापना ही एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम ने की थी। उसका उद्देश्य 1857 जैसी क्रांति को रोकना था। इसके लिए भारतीयों के गुस्से और ब्रिटिश हुकूमत से शिकायत को कम करने के लिए राजनीतिक मंच के रूप में कांग्रेस का गठन किया। इसलिए इसके ज्यादातर सदस्य उस वक्त की ब्रिटिश शिक्षा से तैयार हुए और ब्रिटिश प्रभाव में आए हुए भारतीय थे। आज भी ऐसा ही एक वर्ग कांग्रेस में वर्चस्व बनाए हुए है जो भारतीय संस्कृति और परंपरा से नफरत करता है और बाहरी लोगों की मदद से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। वैसे यह सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति दुनिया को रास नहीं आती और यह बाहरी ताकतें आए दिन यहां के कुछ लोगों को हाथ में लेकर भारत में अराजकता फैलाकर सामाजिक माहौल बिगाड़ना चाहती हैं। भारत में रहने वाला यह वर्ग खुद को स्वतंत्र मानता है और एक अराजकवादी लोकतंत्र में विश्वास रखता है। यही वर्ग कांग्रेस को हथियार की तरह उपयोग करना चाहता है। ऐसे लोगों का साथ लेना सामान्य जनता को गवारा नहीं होता और यही राहुल गांधी की राजनीतिक पहचान बनाने में यह एक बड़ी अडचन नज़र आती है।

यह कहना कि कांग्रेस की कोई विचारधारा है, ठीक नहीं होगा। स्वतंत्रता आंदोलन से पनपी ग्राम स्वराज्य और महात्मा गांधी के रामराज्य की कल्पना को नेहरू ने कभी माना नहीं। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी और सरदार पटेल के जल्दी चले जाने से नेहरू के विचार ही कांग्रेस के विचार हो गए। इसी वजह से कांग्रेस के कई बंटवारे हुए और चुनाव चिन्ह भी बदलते रहे। लेकिन सत्ता में रहने के कारण नेहरू की बात मानी गई। नेहरू पर पाश्चात्य विचारों का प्रभाव था और उन्होंने सारी नीतियां पाश्चात्य विचार और उनकी प्रचलित पद्धति को आधार मानकर ही बनाई, चाहे वह संविधान हो, लोकतंत्र हो, शासन हो या फिर न्याय व्यवस्था हो। आर्थिक-सामाजिक और शिक्षण नीतियां भी वैसी ही बनी। राहुल गांधी जब भारतीय स्थिति की आलोचना करते हैं या उनके बारे में उपहासात्मक बोलते हैं, तब यह भूल जाते है कि आज की सारी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के लिए कांग्रेस की नीतियां ही ज़िम्मेवार रही हैं। हालांकि यह सही है कि आज नेहरू की यह सारी नीतियां दरकिनार हो चुकी हैं और कांग्रेस भी इनको छोड़ चुकी है। आज न समाजवादी समाज रचना की कहीं बात हो रही है न किसी क्षेत्र में सरकार के एकाधिकार की बात है। जब देश कंगाली के कगार पर पहुंच गया था तो नेहरू की आर्थिक नीतियां पूरी तरह उलटनी पड़ी। आज की छद्म धर्मनिरपेक्षता भी कांग्रेस की राजनीति का ही परिणाम है।

लेकिन भारत में चुनावी राजनीति जैसे-जैसे रंग लाने लगी वोटबैंक का महत्व बढ़ता गया और सभी राजनीतिक दल तुष्टीकरण के सहारे वोट-बैंक बनाते गए और कांग्रेस से भी आगे निकल गए। एक ओर जहां हिन्दू को जाति में विभाजित किया गया, वहीं गैर हिन्दुओं को धर्म के नाम पर लामबंद किया गया। भारत के बहुसंख्यक समाज के विचार, परंपरा और संस्कृति को नष्ट करके और उनको बेवकूफ बनाकर चुनाव जीतने के दिन अब नहीं रहे, यह बात स्पष्ट हो गई है। भारत एक प्राचीन विचार है, एक प्राचीन संस्कृति है जो हिन्दू के ही नाम से जानी जाती है उसको नकार कर इस देश का भला नहीं हो सकता। उसे स्वीकार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। भारतीय संस्कृति और इसके मूल विचार की वजह से यह देश स्वभावत: धर्म निरपेक्ष है यह बात अगर समझ आयी तो भारतीय विचार स्वीकारने में आसानी होगी। भारतीय विचार कोई सांप्रदायिक विचार नहीं है ना ही वह किसी और के धर्म को असत्य बताते हैं, न उनके प्रति हिंसा की भावना रखते हैं। मानव जाति का कल्याण ही इस विचार का प्राण है। राहुल गांधी को भी अपनी संस्कृति की ओर मुड़ना होगा और उसमें अपनी पहचान खोजनी होगी।

गांधी आज

उपवास

उपवास को सत्याग्रह के साधन के रूप में काम में लाने में अक्सर बहुत जल्दबाजी और भूलें होती हैं। व्यक्ति के विरुद्ध किए गए सत्याग्रह में उपवास का जिस अंश तक उपयोग किया जा सकता है उस अंश तक समाज अथवा व्यवस्था के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के मुकाबले भी उपवासरूपी सत्याग्रह विवश होने पर ही करना चाहिए। संभव है कि उपवास से विरोधी की न्याय या न होकर उसकी केवल कृपावृत्ति ही जागे, अथवा झगड़े का मुँह काला करत के भाव से वह सत्याग्रही की जिद पूरी कर दे। इसे सत्याग्रह की सफलता नहीं कह सकते। धर्मवृत्ति जागृत व्यक्ति के प्रति किए गए सत्याग्रह में यदि उस व्यक्ति से पहले का कोई निजी अथवा मित्रता का संबंध न हो तो उपवास के उपाय से काम लेना उचित नहीं है। साधारणत: यह कहा जा सकता है कि उपवासरूप सत्याग्रह कुटुंबी, निजी मित्र, गुरु, शिष्य, गुरुभाई आदि निजी तौर पर परिचित लोगों के साथ ही किया जा सकता है। इसी प्रकार समाज अगर अपना ही हो और पहले उसके हाथों हुई सेवा से सत्याग्रही उसका आदरपात्र हो गया हो, तभी उस समाज के अन्याय के प्रति उपवासरूप सत्याग्रह किया जा सकता है। व्यक्ति के प्रति किए जानेवाले सत्याग्रह में निजी अन्याय के लिए तो कभी उपवास करना ही न चाहिए वह व्यक्ति अगर हमारे साथ मित्रता का दावा रखता हो और किसी तीसरे व्यक्ति या वर्ग के या स्वयं अपने प्रति कोई अनुचित आचरण उससे हो रहा हो, तो दूसरे उपाय आजमाने के बाद उपवास किया जा सकता है।

व्यवस्था के विरुद्ध किए गए सत्याग्रह में उपवास आखिरी कदम है। जब सत्याग्रही पराधीन स्थिति में हो और सत्याग्रह के दूसरे उपायों का रास्ता उसके लिए बंद हो, तथा व्यवस्था द्वारा होने वाला अधर्म उसे इतनी पीड़ा दे कि अधर्म या अन्याय को सहन करके जीना सत्वहीन बनकर जीने जैसा हो जाए, तब प्राण छोड़ देने को तैयार होकर ही वह अनशन आरंभ कर सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। इसका निर्णय करने में वह बहुत भावुकता से काम न लेगा, बल्कि उस व्यवस्था को चलाने वाले व्यक्तियों की कठिनाइयों का तथा उनकी पुरानी आदतों का भी उचित विचार करेगा और उनके लिए मुनासिब गुंजाइश रखेगा।

संक्षिप्त समाचार

राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 4 फरवरी को शिविर

रायपुर। रायपुर तहसील के राजस्व प्रकरणों- नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, किसान किताब, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र , निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु 4 फरवरी को तहसील कार्यालय रायपुर में सवेरे 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने शिविर में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारीयों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए है।

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को दो पालियों में होगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2022 दो पालियों में 12 फरवरी को सुबह 10 से 12 बजे तक तथा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक आयोग द्वारा निर्धारित (57) परीक्षा केन्द्रो में आयोजित की जाएगी। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा केन्द्रों हेतु परिवहन अधिकारी और उडन्दस्ता प्रभारी नियुक्त किया है। परीक्षा के दौरान आबंटित परीक्षा केन्द्रों में अनैतिक कार्यो की रोकथाम हेतु पर्यवेक्षक सतत् निरीक्षण करेंगे। परीक्षा के दौरान सभी परीक्षार्थियों एवं अधिकारियों-कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के दिशा निर्देशानुसार सोशल डिस्टेसिंग, सेनेटाईजेशन, मास्क पहनना एवं अन्य सभी दिशा निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।

तृतीय लिंग विमर्श पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमीनार आज से

रायपुर। मैट्स यूनिवर्सिटी, रायपुर के हिन्दी विभाग द्वारा तृतीय लिंग विमर्श कल, आज और कल विषय दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया जा रहा है। देश व प्रदेश के उभयलिंगी समुदाय के उत्थान के उद्देश्य से आयोजित इस सेमीनार में छत्तीसगढ़ सहित देश व विदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार, विषय विशेषज्ञ तथा तृतीय लिंग समुदाय के प्रतिनिधिगण हिस्सा ले रहे हैं। तृतीय लिंग विमर्श पर आयोजित किया जाने वाला यह छत्तीसगढ़ का प्रथम अंतरराष्ट्रीय सेमीनार है। मैट्स यूनिवर्सिटी के हिन्दी विभाग की विभागाध्यक्ष एवं सेमीनार की संयोजक डॉ. रेशमा अंसारी ने बताया कि इस सेमीनार का आयोजन 3 एवं 4 फरवरी 2023 को किया जा रहा है। इस सेमीनार में मुख्य अतिथि के रूप में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केशरी लाल वर्मा, अमेरिका के वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. प्रेम भारद्वाज, तृतीय लिंग विमर्श की प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. लता अग्रवाल (भोपाल), विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान, प्रयागराज उत्तरप्रदेश के अध्यक्ष डॉ. शेख शहाबुद्दीन, कॉटन यूनिवर्सिटी, गोवाहाटी, असम की प्राध्यापक डॉ. नूरजहां रहमतुल्ला, छत्तीसगढ़ तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड की सदस्य एवं पं. रविशंकर शुक्ल सम्मान से सम्मानित सुश्री विद्या राजपूत, छत्तीसगढ़ तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड की सदस्य सुश्री रवीना बरिहा और देश की प्रथम उभयलिंगी ज्योतिषी भैरवी अमरानी आमंत्रित हैं।

मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लीनिक से 1.42 लाख से ज्यादा महिलाओं का हुआ निःशुल्क इलाज

रायपुर। मुख्यमंत्री दाई-दीदी मोबाइल क्लीनिकों के माध्यम से अब तक करीब 1812 कैम्प लगाएं जा चुके हैं। दाई-दीदी क्लीनिक के माध्यम से रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई नगर निगम क्षेत्र की स्लम बस्तियों में रहने वाली 1 लाख 42 हजार 582 महिलाओं एवं बच्चियों का उनके घर के पास ही दाई-दीदी क्लीनिक कैंप के माध्यम से इलाज किया गया है गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लिनिक योजना संचालित है। योजना के तहत दाई-दीदी क्लिनिक की मोबाइल मेडिकल यूनिट के वाहन में महिला चिकित्सकों और महिला स्टॉफ की टीम पहुंचती है तथा जरूरतमंद महिलाओं एवं बच्चियों की विभिन्न बीमारियों का निःशुल्क इलाज करती है। इन मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा 26 जहार 717 महिलाओं का लैब टेस्ट किया गया तथा 1 लाख 36 हजार 95 महिलाओं को निःशुल्क दवाईयां दी गई। पहले गरीब स्लम क्षेत्र में रहने वाली तथा मेहनत मजदूरी करने वाली ऐसी महिलाएं जो समयाभाव या अन्य कई कारणों से अपना इलाज नहीं करा पा रही थी परन्तु अब दाई-दीदी क्लीनिक से उन्हें इलाज की सुविधा घर के पास ही महिला चिकित्सकों और चिकित्सा स्टॉफ के माध्यम से मिल रही है।

राजीव भवन रायपुर में स्व. चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में स्व. चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री संगठन अमरजीत चावला, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, किसान कांग्रेस अध्यक्ष रामबिलास साहू, मेहमूद अली, भवानी मरकाम कांग्रेसजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जी आगे परीक्षा है प्लीज धरना स्थल हटवा दीजिए

हस्ताक्षर अभियान के मार्फत बच्चों ने लगाई गुहार- दुबे

रायपुर। बूढ़ापारा धरना स्थल स्कूल कालेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अभिशप्त बन चुका है। परेशान बच्चों व पालकों को जब जानकारी मिली की नगर निगम के अध्यक्ष प्रमोद दुबे ने धरना स्थल को पूर्णतः हटाने की मांग को लेकर मुहिम शुरू कर दी है,तो उन्होने श्री दुबे से स्वंय संपर्क साधा और कहा कि वे पूरी तरह से उनके साथ हैं,जहां भी कहेंगे साथ चलने तैयार हैं बस आप धरना स्थल को बंद करवा दें। बच्चों के भावनात्मक बातों से साफ लग रहा था कि वे इस पीड़ा को कब से झेल रहे हैं। इसलिए अब तय कर रखा है कि अभियान अपने अंजाम को पूरा करने के बाद ही खत्म होगा।

स्कूल के बच्चों ने मुख्यमंत्री के नाम संदेश भेजा संदेश में लिखा सीएम साहब प्लीज परीक्षा नजदीक है धरना स्थल हटवा दें । नगर निगम के अध्यक्ष प्रमोद दुबे ने बताया कि आज विभिन्न शाला की छात्राओं ने स्वयं आकर के लिखित में हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया कि उनकी परीक्षा नजदीक है और धरना स्थल के चलते सभी स्कूल कॉलेज उसी मार्ग पर हैं इसलिए संदेश के माध्यम से उन्होंने आग्रह किया,, कि सी एम साहब प्लीज हमारे भविष्य को ध्यान में रख धरना स्थल को तत्काल हटवाने की कृपा करें । प्रमोद दुबे ने बताया कि आज स्कूली बच्चों से हस्ताक्षर अभियान के दौरान सैकड़ों बच्चे स्कूल जाने के पहले रुक रुक कर हस्ताक्षर किए।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे कलेक्टर सर,, मुख्यमंत्री जी ,,प्रभारी मंत्री जी या सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों के समक्ष जाकर आग्रह कर सकते हैं । बच्चों की व्यथा यह है कि विगत 2 माह में 15 बार धरना स्थल बंद होने के चलते एक्स्ट्रा क्लास का भी सहारा लेना पड़ रहा है। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू हो चुकी है। इसी प्रकार महंत कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बताया कि उनके परीक्षा सेमेस्टर सिस्टम में होने के कारण नवंबर माह में लगातार आंदोलन के चलते रहने के कारण बहुत व्यवधान का सामना करना पड़ा।

स्कूल के बच्चों ने अलग-अलग ढंग से मुख्यमंत्री को संबोधित किया किसी ने लिखा है कका हम पर दया करो,, किसी ने लिखा है भूपेश अंकल आपके ऊपर भरोसा है,, इस प्रकार के अनेक संबोधन कर उनसे आग्रह करते हुए यथाशीघ्र धरना स्थल को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की मांग बच्चों ने रखी है । आज विभिन्न स्कूलों के लगभग 300 से ज्यादा बच्चे हस्ताक्षर किए।

तीन दिन में बुढ़ातालाब के पास धरना प्रदर्शन स्थल नहीं हटा तो बाउंड्रीवाल बना देंगे- महापौर

रायपुर नगर पालिक निगम के महापौर ऐजाज ढेबर ने बुधवार को ऐलान किया कि अगर तीन दिन में बूढ़ापारा धरना स्थल से प्रदर्शन नहीं हटा तो निगम सरकार वहां बॉउंड्रीवॉल का निर्माण करायेगी। आम लोगों को हो रही दिक्कतों के चलते महापौर ने यह बात कही। जिला कलेक्टर से मुलाकात करने के बाद महापौर एजाज़ ढेबर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि धरना प्रदर्शन स्थल रायपुर निगम की जमीन है, लेकिन वहां आये दिन कोई न कोई धरना प्रदर्शन होता है, जिसके चलते आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि स्कूली बच्चे 2 घंटे लेट से अपने घर पहुँचते हैं, अंतिम संस्कार के लिये ले जाई जा रही अर्थियों को घंटो इन्तजार करना पड़ता है। धरना स्थल के कारण हमारे इंडोर स्टेडियम का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता।

मूक-बधिर बच्चों ने जीवन का एक नया पाठ पढ़ाया- डॉ.भट्टर

रायपुर। अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल के मूक-बधिर बच्चों से मिलने के बाद सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.अशोक भट्टर ने कहा कि मुझे आज जीवन का एक नया पाठ पढ़ने को मिला है। डॉ. भट्टर ने कहा कि इन बच्चों ने बता दिया है कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए।

दृढ़ इच्छाशक्ति और कठिन मेहनत से जीवन में हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बोल और सुन नहीं सकने के बाद भी ये बच्चे जिस लगन और मेहनत से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वह अनुकरणीय है। डॉ. भट्टर ने यहां बजाज कालोनी (राजेन्द्र नगर) में स्थित अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल के पांच बच्चों को एक साल के लिए गोद लिया। इन पांच बच्चों की शिक्षा-दीक्षा में जो भी राशि लगेगी, वह डॉ. भट्टर वहन करेंगे। रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने इस अवसर पर कहा कि अर्पण कल्याण समिति मूक-बधिर बच्चों को निःशुल्क उच्चस्तरीय शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रही है, वह प्रशंसनीय है। श्री दुबे ने कहा कि डॉ. भट्टर ने पांच बच्चों को गोद लेकर जो नेक कार्य किया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं।

सभापति श्री दुबे ने समाज के प्रबुद्धजनों से अपील करते हुए कहा कि दिव्यांग बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए वे स्वस्फूर्त आगे आएं। इस स्कूल में निशुल्क सेवा दें रहीं स्पीच थेरेपिस्ट डॉ. रूचिरा राज पांडेय ने कहा कि पिछले सात माह में यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों के शिक्षा के स्तर और व्यक्तित्व में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसके लिए प्राचार्य कमलेश शुक्ला और उसकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मोदी सरकार की एक और पहल

रायपुर। राष्ट्रीय महिलामोर्चा श्रीमती पदमाजा जी ने छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा की वर्चुअल बैठक का उद्घोधन किया जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के द्वारा महिला मोर्चा की ई केंद्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की ई केंद्र शुरू करने का प्रस्ताव मोदी जी के सरकार के द्वारा रखा है, जो सभी जिलों में फैलेगा और अंततः भारत के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। शिक्षा के संबंध में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ जीवन में अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के लिए केंद्र लड़कियों और महिलाओं के लिए मशाल वाहक होगा। इसका उद्देश्य देश भर में डिजिटल रूप से और भौतिक केंद्रों के माध्यम से महिलाओं तक उनकी शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और अधिकारिता तक पहुंचना है। महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा महिला केंद्रित पहल। महत्व देश के दूरस्थ जिलों में भी महिलाओं तक पहुंचना। महिलाओं की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए है । उक्त बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत जी के अलावा प्रदेश के सभी पदाधिकारी सभी जिला अध्यक्ष उपस्थित थे।

धान खरीदी की व्यवस्थाओं से खिल उठे किसानों के चेहरे

बिलासपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में जिले में समर्थन मूल्य पर 1 नवम्बर से शुरू धान खरीदी अभियान के तहत 5 लाख 13 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी की गई जो कि लक्ष्य का 94 फीसदी है। किसानों को सहूलियत देते हुए 138 धान खरीदी केन्द्रो के माध्यम से धान खरीदी की गई। यह अब तक का बिलासपुर जिले में सर्वाधिक धान खरीदी का रिकार्ड है। गतवर्ष की अपेक्षा इस बार किसानों से अधिक धान खरीदी की गई है। इस वर्ष धान खरीदी की समुचित व्यवस्थाओं से किसानों के चेहरे खिल उठे । उन्होंने शासन की खरीदी की व्यवस्था की तारीफ करते हुए उनके प्रति आभार जताया। वन अधिकार पत्र धारक 811 किसानों से 48 हजार क्विंटल धान की खरीदी इस वर्ष की गई है। खाद्य विभाग के अधिकारियो ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में जिले में 1 लाख 19 हजार 150 किसानों से 5 लाख 13 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। जिसके एवज में 104 करोड़ 30 लाख रूपए का ऑन लाईन भुगतान उनके खातों में किया गया है। जिले में पंजीकृत किसानों की संख्या 1 लाख 23 हजार 366 है। इसके साथ ही 97 प्रतिशत् धान का उठाव भी किया जा चुका है। जिले के सहकारी बैंक की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से किसानों के खाते में 104 करोड़ 30 लाख रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जा चुका है। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने धान खरीदी अभियान को सफल बनाने पर अभियान में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है।

प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने केंद्र व राज्य सरकार करेंगे संयुक्त प्रयास

- **मंत्री अमरजीत भगत की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ संस्कृति-पुरातत्व विभाग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के मध्य समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर**

रायपुर। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने, संरक्षण व संवर्धन के लिए संयुक्त रूप से केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य करेंगे। इसके लिए आज मंत्री श्री अमरजीत भगत की उपस्थिति में संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय रायपुर तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र नई दिल्ली के मध्य परस्पर समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) में हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र द्वारा स्थानीय छात्रों, पर्यटकों, शोधार्थियों एवं जनमानस को उनकी पुरा-संस्कृति के वास्तविक पक्षों से परिचित कराने हेतु विश्व व भारत की शैल कला के साथ छत्तीसगढ़ की शैल कला पर महत्न घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में अलग से दीर्घा स्थापित की जाएगी। साथ ही दोनों संस्थाओं की विभिन्न अकादमिक कार्यक्रमों-परियोजनाओं जैसे शोध प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधनों का संकलन, सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण तथा राज्य संरक्षित शैलाश्रयों के संरक्षण-परिरक्षण जैसे कार्यों में सहायक होगी। संस्कृति मंत्री श्री भगत ने इस समझौते पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की धरोहरों और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में यह समझौता ज्ञापन महत्वपूर्ण है। संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को सहेजने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्कृति विभाग द्वारा इस दौरान केन्द्रीय प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ की राजकीय गमछे से स्वागत किया गया। इस मौके पर संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक विवेक आचार्य, उप संचालक डॉ. पी. सी. पारख, उत्खनन सहायक प्रवीण तिर्की, डॉ. राजीव मिंज और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आई.जी.एन.सी.ए.) नई दिल्ली से शैलकला विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. रमाकर पंत, सहायक प्राध्यापक डॉ. दिलीप सन्त, परियोजना सहायक जाकिर खान व परियोजना सहयोगी प्रवीण सी.के. उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ ने खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ाए कदम

- **मुख्यमंत्री सुपोषण अभियानः 2.65 लाख बच्चे हुए कुपोषण मुक्त**
- **एक लाख 50 हजार महिलाएं एनीमिया से मुक्त**

रायपुर। प्रदेश में कुपोषण के कुचक्र को तोड़ने के लिए चलाये जा रहे प्रदेशव्यापी 'मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान' से कुपोषण के दायरे में आने वाले 4 लाख 34 हजार बच्चों को पिछले चार सालों में 2 लाख 65 हजार बच्चों को कुपोषण के दायरे से बाहर लाने में सफलता मिली है। अभियान के तहत एक लाख 50 हजार महिलाओं को एनीमिया से मुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में कुपोषण के आंकड़ों को गंभीरता से लेते हुए 02 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरूआत की गई थी। अभियान के तहत छह वर्ष तक के कुपोषित बच्चों और 15 से 49 वर्ष तक की एनीमिक महिलाओं गर्म पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अलावा राज्य सरकार ने गर्भस्थ शिशुओं से लेकर सुरक्षित प्रसव, माताओं और शिशुओं के स्वस्थ विकास के विभिन्न पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया जिससे मातृत्व मृत्यु दर भी 159 से घटकर 137 हो गई है। दूसरी संतान भी बेटी होने की स्थिति में किसी भी तरह की मदद का प्रावधान पूर्व में नहीं था। इस अंतर को पाटने के लिए राज्य सरकार ने 'कौशल्या मातृत्व सहायता योजना' शुरू की। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को एकमुश्त 5 हजार रूपए प्रदान किया जा रहा है। इससे गर्भवती माता और उसके बच्चे के पोषण सुरक्षा के लिए एक बड़ी मदद मिल रही है। राज्य सरकार ने महिलाओं एवं बच्चों की पोषण सुरक्षा के लिए बड़े और समन्वित कदम उठाए हैं। प्रदेश में कोई परिवार भूखा न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। राज्य सरकार ने 2011 की जनगणना के अनुसार 'सार्वभौम पीडीएस' के तहत 2 करोड़ 61 लाख हितग्राहियों को अर्थात् शत-प्रतिशत खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य पूरा कर लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 64 लाख अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक निर्धारित मासिक पात्रता एवं अतिरिक्त पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किया।

इसे आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वर्ष जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क प्रदाय करने की घोषणा की है। प्रदेश ने खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर कदम बढ़ाए हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय खान-पान की विशेषताओं और रुचियों का विशेष ध्यान रखते हुए पोषण सुरक्षा के लिए आयरन फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का 12 जिलों में 'मध्याह्न भोजन योजना' तथा 'पूरक पोषण आहार योजना' हेतु वितरण किया जा रहा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ के प्रखर पत्रकार और पूर्व सांसद स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और डोंगरगांव विधायक श्री दलेश्वर साहू भी उपस्थित थे।

स्मार्ट बिजली मीटर से उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर सुविधा

बिजली उपभोक्ताओं को अधिक सशक्त बनाएगी स्मार्ट मीटर व्यवस्था

- **एनपीटीआई ने शुरू किया अभियंताओं के लिए दूसरे दौर का प्रशिक्षण**

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी के प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग की दिशा में पॉवर कंपनी तेजी से काम कर रही है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। यह बातें मुख्य अभियंता (परियोजना) राजेन्द्र प्रसाद ने राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) दुर्गापुर द्वारा आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर कही। एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) पर केन्द्रित दूसरे चरण के प्रशिक्षण में 40 अभियंता हिस्सा ले रहे हैं। मास्टर ट्रेनरों द्वारा इस दौरान स्मार्ट बिजली मीटरों की स्थापना , संचालन तथा उससे जुड़ी अधोसंचरनाओं के समन्वय के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। गुढ़ियारी स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सीटीआई) में 01-03 फरवरी तक आयोजित कार्यक्रम में एनपीटीआई दुर्गापुर के उप संचालक डॉ सी भट्टाचार्य ने बताया कि प्रशिक्षण में विद्युत वितरण हानि को कम करने में स्मार्ट बिजली मीटर की उपयोगिता के संबंध में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक कारगर उपाए साबित होगा।

मुख्य अभियंता (प्रशिक्षण) श्री डी एस भगत ने कहा कि आने वाला समय स्मार्ट कार्य शैली के साथ ही स्मार्ट मीटर का है ऐसे में हमारे अभियंताओं को इसके लिए तैयार होना होगा। इसी कड़ी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायपुर में पहले चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम 3-5 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया था। इसके अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में भी ये प्रशिक्षण आयोजित जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि आरडीएसएस योजना का देशभर में वितरण हानि कम करने तथा उपभोक्ताओं के हित में बिजली मीटरिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने का लक्ष्य है। एनपीटीआई द्वारा रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत देशभर की वितरण कंपनी से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

संक्षिप्त ख़बरें

छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा का दौरा कार्यक्रम आज से

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा 03 फरवरी 2023 शुक्रवार को दोपहर 1.35 बजे इंडिगो की नियमित विमान सेवा द्वारा नई दिल्ली से रायपुर विमानतल, पहुंचेंगे एवं सर्किट हाउस जायेंगे। दोपहर 2 बजे राजीव भवन, रायपुर में लीडरशिप डेव्हलपमेन्ट मिशन (ष्ठरू) के तहत आयोजित बैठक में भाग लेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा 04 फरवरी 2023 शनिवार को प्रात: 11 बजे सर्किट हाउस, रायपुर में विधायकों के साथ बैठक एवं चर्चा करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा 06 फरवरी 2023 सोमवार को रात्रि 9 बजे इंडिगो की नियमित विमान सेवा द्वारा रायपुर से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

कस्टम मिलिंग के लिए 91 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव

रायपुर। प्रदेश में धान खरीदी के अंतिम तिथि के पश्चात् अब कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स द्वारा तेजी के साथ धान का उठाव शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश की पहल पर पिछले वर्ष की तर्ज पर इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव शुरू किया गया था, जिसके चलते राज्य सरकार को परिवहन व्यय में काफी कमी आयी है। इसके साथ ही धान खरीदी के बाद धान उठाव की लंबी प्रक्रिया से भी निजात मिली है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 23 लाख 82 हजार से अधिक किसानों से 31 जनवरी 2023 तक 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। किसानों को धान खरीदी के एवज में भुगतान हेतु बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत मार्कफेड द्वारा अपैक्स बैंक को 22 हजार 67 करोड़ रूपए जारी किया गया है। अब तक कुल धान खरीदी 107.53 लाख मीट्रिक टन में से कस्टम मिलिंग के लिए 97 लाख 20 हजार मीट्रिक टन धान उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 91 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव कर लिया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य में बीते चार सालों में धान खरीदी की व्यवस्था को इतना सुदृढ़ और बेहतर किया गया है कि किसानों को धान बेचने और भुगतान प्राप्त करने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है।

कोरोना काल में शराब से वसूली पर कांग्रेस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है- चंद्राकर

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व प्रदेश के पूर्व केबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर ने कोरोना काल में देशी शराब पर 10 रुपए प्रति बोतल व विदेशी शराब पर 10 प्रतिशत सेस लगाकर करोड़ों रुपए की कमाई करने के बारे में हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के 10 माह बाद भी राज्य सरकार द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार ने आखिर क्या गड़बड़ी की है कि वह हाईकोर्ट में अपना जवाब इतना समय बीत जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना के नाम पर शराब से करोड़ों रुपए अर्जित किये। लेकिन कोरोना से बचाव के लिए इस राशि का न तो उपयोग किया गया और न ही यह रकम स्वास्थ्य विभाग को अंतरित की गई। यह राशि का दुरुपयोग है। जिस प्रयोजन से सरकार ने कोरोना काल में शराब से अतिरिक्त टैक्स लिया, उस पर ही इसे व्यय किया जा सकता है। जो कि राज्य सरकार ने नहीं किया।

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए टैक्स वसूलने के बाद उसका स्वास्थ्य के क्षेत्र में सदुपयोग नहीं किये जाने की अनियमितता के विरुद्ध उन्होंने मार्च 2022 में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जिस पर राज्य सरकार ने अब तक जवाब नहीं दिया है। राज्य सरकार न्यायालय के नोटिस को गंभीरता से नहीं ले रही है या वह कुछ छुपाना चाहती है। यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने विधि विरुद्ध कार्य किया है। इसलिए वह जवाब देने से बच रही है।

बृजमोहन अग्रवाल अजय चंद्राकर पीएम केयर फंड का हिसाब किताब जनता को बताये

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 के दौरान खर्च की गई राशि का हिसाब किताब पूछने वाले बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर को प्रदेश की जनता को पीएम केयर फंड का हिसाब किताब बताना चाहिए प्रदेश के 9 भाजपा सांसद राज्यसभा सदस्य ने सांसद निधि से करोड़ों रुपए की राशि पीएम केयर फंड में जमा कराये।इसके अलावा मोदी सरकार ने दबाव पूर्वक प्रदेश की जनता की हित मे खर्च होने वाली सीएसआर फ़ंड की सैकड़ो करोड़ रूपये भी पीएम केयर फंड में जबर्दस्ती जमा कराये। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि प्रदेश से पीएम केयर फंड में जमा हुई सैकड़ो करोड़ की राशि कहां खर्च हुई? इतनी मदद के बावजूद मोदी सरकार की मनमानी के चलते देश की जनता पैदल सड़कों पर भटकने मजबूर थे समय पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया सही समय पर वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की गई प्रदेश और देश की जनता भाजपा से पीएम केयर फंड का हिसाब जानना चाहती है जिसका हिसाब देने के लिए केंद्र सरकार बच रही है इसे स्पष्ट हो जाता है कि बड़ा घोटाला पीएम केयर फंड में भाजपा की सरकार ने किया है।उस दौरान खरीदी गई वेंटिलेटर की क्वालिटी खराब थी महंगे दरों पर वेंटिलेटर खरीदा गया उस दौरान केंद्र की भाजपा सरकार का मुख्य एजेंडा घोटाला करना ही रहा है।

हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में जनता कर रही है भूपेश सरकार की योजना की तारीफ

रायपुर। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आज आठवे दिन भी जोर-शोर से चला। इस दौरान लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं से हाथ मिला कर जनता भूपेश सरकार की योजना की तारीफ कर रही है।भूपेश सरकार की न्याय योजना से आम लोग के जीवन मे परिवर्तन आया।मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियां वादाखिलाफी और तानाशाही रवैया के चलते उत्पन्न हुई रोजगार संकट, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल की लूट, खाद्य सामग्रियों में लगाई गई जीएसटी के साथ अन्य समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, भिलाई, बेमेतरा, राजनांदगांव शहर, राजनांदगांव ग्रामीण, कवर्धा, जगदलपुर शहर, बस्तर ग्रामीण, सुकमा, नारायणपुर, कोण्डगांव, बीजापुर, सहित सभी ब्लाको में हाथ से हाथ से जोड़ो यात्रा हुई।

अल्पसंख्यक समाज के लोग मोदी से जुड़ना चाहते हैं: जमाल सिद्दीकी

रायपुर। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने आए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने आज यहां भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जोड़ रहे हैं जो शोषित वंचित हैं। उन लोगों को जोड़ रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक दलों की हकीकत को समझते हैं और मोदी जी की नीतियों को जानते हैं कि मोदी जी देश का विकास चाहते हैं। देशवासियों का विकास चाहते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाने पर पार्टी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। हम नड्डा जी के संगठन नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति धन्यवाद

दिया गया कि जी.20 की 200 बैठकें भारत के 56 शहरों में करा रहे हैं। दुनिया के नेता हमारी संस्कृति से वाकिफ होंगे। मोदी जी भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। हम अतिथियों का स्वागत सूफी संगीत से करेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरी सरकारों ने सूफी संगीत को खत्म कर आतंकवाद पकड़ा दिया। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना के दूसरे वेरीएंट हैं। जिन्ना ने जिस तरह अपने हित के लिए, अपनी कुर्सी के लिए देश को बांटा, उसी तरह ओवैसी अपनी कुर्सी के लिए देश की गंगा जमनी तहज़ीब को तोड़ रहे हैं। देश की एकता और अखंडता को तोड़ रहे हैं। देश में अल्पसंख्यक मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी, इस पर प्रकाश डालते हुए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि हमने देश भर में 60 लोकसभा सीटें चिन्हित की हैं, जहां अल्पसंख्यक मोर्चा प्रवास करेगा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मोदी जी से जोड़ेंगे। अल्पसंख्यक समाज को मोदी मित्र बनाया जाएगा। चुनावी वर्ष में छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति क्यों आयोजित की गई, इस पर श्री सिद्दीकी ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एक अच्छा राज्य है। यहां के लोग बहुत अच्छे हैं। इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चा के समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के लोगों से मिलना चाहा, इसलिए यहां बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि कि राष्ट्रीय पदाधिकारी मंडलों की बैठक ले रहे हैं। यह संगठन के कार्य हैं। हमारा ये दौरा चुनाव के मद्देनज़र नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हमें अल्पसंख्यक समाज में जाना है। उनसे मिलना है।

हाट-बाजार क्लीनिकों में 82 लाख लोगों का इलाज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वनांचलों और ग्रामीण इलाकों के हाट-बाजारों में स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीमों द्वारा अब तक कुल 81 लाख 89 हजार 806 लोगों को इलाज मुहैया कराया गया है। मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना के माध्यम से प्रदेश के 1749 हाट-बाजारों में क्लीनिक लगाकर लोगों की नि:शुल्क जांच व उपचार कर दवाईयां दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा योजना की शुरूआत के बाद से अब तक प्रदेश भर में कुल एक लाख 44 हजार 962 हाट-बाजार क्लीनिक आयोजित कर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

योजना के अंतर्गत राज्य में 429 डेडिकेटेड ब्रांडिंग वाहन तथा चिकित्सा दलों के माध्यम से दूरस्थ अंचलों में लोगों का इलाज किया जा रहा है। हाट-बाजार क्लीनिकों में जरूरतमंदों को नि:शुल्क उपचार, चिकित्सकीय परामर्श और दवाईयां उपलब्ध कराने के साथ ही मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा मलेरिया, एचआईव्ही, मधुमेह, एनीमिया, टीबी, कुष्ठ रोग, उच्च रक्तचाप और नेत्र विकारों की जांच भी की जा रही है। इन क्लीनिकों में शिशुओं और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी किया जा रहा है। हाट-बाजार क्लीनिकों में ओ.पी.डी. आधारित

आठ प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जांच के बाद व्याधिग्रस्त पाए गए लोगों को नि:शुल्क दवाईयां भी दी जाती हैं। जिन मरीज़ों को उच्च स्तरीय जाँच अथवा उपचार की आवश्यकता होती है उन्हें हाट-बाज़ार क्लीनिक से सीधे स्वास्थ्य केंद्र में रिफर भी किया जा रहा है ताकि उनका सम्पूर्ण उपचार सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 23 लाख 13 हजार 461 लोगों के उच्च रक्तचाप, 19 लाख 88 हजार 675 लोगों की मधुमेह, छह लाख 19 हजार 015 लोगों की मलेरिया जांच, चार लाख 73 हजार 560 लोगों की रक्त-अल्पता (एनीमिया) और दो लाख 90 हजार 047 लोगों में नेत्र विकारों की जांच की गई है।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

मोदी सरकार ने गरीबों पर प्रहार अमीरों को राहत दिया-कांग्रेस

रायपुर। मोदी सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में देश के आम आदमी की उपेक्षा की गयी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार ने ज्यादा कमाई वालों को राहत देने के लिये बजट बनाया है। 7 लाख तक आमदनी वालो को टैक्स में राहत देने का प्रावधान कर अपनी पीठ थपथपाने वाले मोदी सरकार बतायें देश में कितने लोगों की आमदनी 7 लाख रू. से अधिक है? जब आमदनी 7 लाख से अधिक होगी तब ही तो छूट का लाभ मिलेगा। सरकार बताये लोग 7 लाख कैसे कमायेंगे? एक तरफ तो मनरेगा के बजट में 10 हजार करोड़ की कटौती कर रहे है, मनरेगा के मजदूर की दिहाड़ी प्रतिदिन 204 रू. है। उनको साल में 150 दिन काम मिलता है, उनकी सालाना आय लगभग तीस हजार रू. है। कितनी बड़ी विडंबना है कि मोदी सरकार के बजट में तीस हजार सालाना कमाने वालों के लिये कटौती कर रही है तथा 7 लाख कमाने वालो के हितों का ध्यान रख रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हाल ही में एनएसओ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि देश में किसानों की औसत आमदनी मात्र ?27 प्रतिदिन रह गई है, जो मनरेगा मजदूरी से भी कम है।

अडानी समूह के घपले बाजी की ईडी और सीबीआई से जांच कराई जाये

रायपुर। कांग्रेस ने मांग किया कि हिंडनबर्ग रिर्पोट और अडानी समूह की धोखाधड़ी पर केन्द्र सरकार श्वेत पत्र जारी करें। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अडानी समूह की कंपनियों में देश की सबसे सरक्षित मानी जाने वाली निवेश कंपनिया एलआईसी और एसबीआई ने भी पैसा लगाया है। अडानी समूह में एलआईसी और सीबीआई का भी पैसा लगा है। यहां पर एलआईसी के 27 करोड़ पालिसी होल्डर तथा एसबीआई के यह करोड़ खाता धारकों के विश्वास और हितों का सवाल है। यह भारत सरकार की विश्वसनीयता पर भी सवाल है। मोदी सरकार अपनी समूह के इस घपलेबाजी की ईडी और सेबी से जांच कराये। मोदी सरकार अडानी के घपले की जांच ईडी से क्यों नहीं करवा रही है? क्या ईडी की स्थापना सिर्फ भाजपा के राजनैतिक विरोधियो के खिलाफ षडयंत्र करने के लिये किया गया है? प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडेनबर्ग ने एक जारी रिपोर्ट में बताया कि अडाणी ग्रुप की सभी 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर काफी ज्यादा कर्ज है। अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर 85 प्रतिशत से ज्यादा ओवरवैल्यूड भी हैं।

नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में शिथिलता बरतने पर अतिरिक्त तहसीलदार को शो कॉज नोटिस

बिलासपुर। कलेक्टर सौरभकुमार ने विवादित नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में शिथिलता बरतने पर जिला मुख्यालय के अतिरिक्त तहसीलदार कृष्ण कुमार जायसवाल को शौ कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिले में लंबित कुल 247 विवादित नामांतरण प्रकरणों में से अकेले श्री जायसवाल के कोर्ट में 98 मामले लंबित है। कलेक्टर आज यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की लम्बी बैठक लेकर राजस्व से जुड़े विभिन्न मामलों गहन समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत पात्र तमाम हितग्राहियों की सूची जिला प्रशासन की वेबसाईट में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने को कहा है। कलेक्टर सौरभकुमार ने राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत पूर्व में किये गये सर्वे की सूची एक सप्ताह के भीतर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने नवीन सर्वे की सूची भी प्रकाशित करनें के निर्देश दिए। नगरीय इलाकों में भी वन अधिकार पट्टा प्रदान करने के लिए एक दफा फिर सर्वे किया जाये ताकि राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत उन्हें पट्टे वितरित किया जा सके। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक योजना के अंतर्गत 2273 नवीन आवेदन आये हैं। उन्हें स्वीकृत किया जा चुका है। इसके पहले लगभग 35 हजार हितग्राहियों को योजना का फायदा मिल रहा है।

अमृतकाल में देश में कथित ऐतिहासिक विकास का दावा असत्य- मुख्यमंत्री

रायपुर। 1 फरवरी को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट 2023 संसद में पेश किया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को ही आम बजट 2023 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह निर्मला सीतारमण का निर्मम बजट है. छत्तीसगढ़ के लिए इस निराशाजनक बजट में कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार के ऐतिहासिक विकास के दावों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर निशाना साधा है। सीएम बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि वास्तविकता यह है कि यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में जेडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर, एनडीए के विगत 9 साल के कार्यकाल की तुलना में अधिक रही है। एनडीए सरकार बनाम यूपीए सरकार की तुलना करते हुए उन्होंने मनमोहन सरकार के 10 साल के कार्यकाल में जीडीपी की औसत आंकड़ों को भी वर्षवार ट्वीट कर प्रस्तुत किया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विट के जरिये बताया है कि जैसे 2019 से 2022 के बीच कोविड संकट आया था, वैसे ही 2006 से 2008 के बीच वैश्विक मंदी भी आयी थी. लेकिन डॉ मनमोहन सिंह जी के कुशल आर्थिक प्रबंधन के कारण ,एनडीए की वृद्धि दर पर प्रभाव नहीं पड़ा।

भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आरक्षण को लेकर जा रहे थे सीएम हाउस घेराव करने

रायपुर। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण के मामले पर सीएम हाउस घेरने जा रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बूढ़ातालाब धरना स्थल के समीप ही रोक दिया। घेराव कार्यक्रम में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर भी शामिल हुए। बाद में जिला प्रशासन के अफसरों ने उनका ज्ञापन लिया। अनुसूचित जाति के लिए तय आरक्षण की सीमा को लेकर कार्यकर्ता खफा है। हालांकि प्रदेश में आरक्षण का विवाद अभी कोर्ट में है। इसके चलते अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस घेराव का फैसला लिया था। घेराव में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर भी शामिल हुए। धरना स्थल पर अपने संबोधन में चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार के नेता बाबू जगदीप प्रसाद कुशवाहा की भी जयंती है। सौ में से नब्बे शोषित, शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाठ में 90 फीसदी हिस्सा हमारा है। उन्होंने एक और नारा दिया था। 90 पर 10 शासन नहीं चलेगा। लेकिन बुरा यह है कि उनके जाने के बाद भी आज भी 90 फीसदी लोगों पर भी 10 फीसदी हावी है। उन्होंने कहा कि अधिकार अगर मांगने से मिलते तो हजारों साल से आज इस देश में हमलोग अधिकारों को मांग रहे, चिल्ला रहे, रो रहे अन्याय सह रहे, लेकिन आज तक हमलोगों को अधिकार नहीं मिला।

छत्तीसगढ़ में वेटलैण्डों को चिन्हांकित कर उनके विकास के लिए तेजी से हो कार्य- अकबर

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में सम्बोधित करते हुए कहा कि वेटलैण्ड (आर्द्रभूमि) को पारिस्थितिकीय तथा स्वस्थ्य पर्यावरण के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। राज्य में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वेटलैण्डों के विकास के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही जारी है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री अकबर ने इस दौरान छत्तीसगढ़ में वेटलैण्डों (आर्द्रभूमि) को चिन्हांकित कर उनके विकास के लिए तेजी से कार्य करने के लिए विशेष जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में सर्वेक्षण उपरांत वेटलैण्डों का शीघ्रता से सूचीबद्ध करने और महत्वपूर्ण वेटलैण्डों को रामसर स्थल के रूप में घोषित कराने विशेष पहल हो। कार्यक्रम को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख संजय शुक्ला, अध्यक्ष राज्य जैव विविधता बोर्ड राकेश चतुर्वेदी तथा राज्य वेटलैण्ड अथॉरिटी के सदस्य सचिव अरूण पांडेय ने भी सम्बोधित किया। वन मंत्री श्री अकबर ने इस दौरान अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरूण पाण्डेय के आलेख पर आधारित प्रकाशित पुस्तिका 'वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों में अभियोज' का विमोचन भी किया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कुल 35 हजार 534 वेटलैण्ड हैं, जिसमें से 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के 7 हजार 711 वेटलैण्ड हैं तथा 2.25 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के 27 हजार 823 वेटलैण्ड हैं। इन समस्त वेटलैण्डों का क्षेत्रफल 3 लाख 37 हजार 966 हेक्टेयर है।

स्वामी आत्मानंद स्कूल के 2 करोड़ रूपए की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण

बच्चों ने एस्ट्रो लैब में मुख्यमंत्री को दिखाया ग्रेविटी का प्रभाव

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड के जामगांव (एम) में स्वामी आत्मानंद स्कूल के 2 करोड़ रूपए की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यहां स्थापित एस्ट्रोलैब भी देखी। यहां पर बच्चों ने मुख्यमंत्री को बताया कि किस तरह से ग्रेविटेशन का प्रभाव अलग-अलग ग्रहों में अलग-अलग पड़ता है।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से चर्चा में कहा कि आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी दी जा रही है जो बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री ने यहां का टेलिस्कोप भी देखा। साथ ही भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा एवं कल्पना चावला आदि के कार्य का डिस्प्ले भी देखा। मुख्यमंत्री स्कूल के फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री

लैब और बायो लैब में भी गए। मुख्यमंत्री ने यहां बच्चों के प्रैक्टिकल भी देखे तथा उनसे प्रश्न भी पूछे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से पूछा कि आपको इस स्कूल में पढ़ाई करके कैसा लग रहा है। बच्चों ने कहा हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यहां आपने सारी सुविधाएं हमें दी हैं। हमारी टीचर बहुत अच्छे हैं और हमें अत्याधुनिक तरीके से पढ़ाई कराई जाती है। हमें स्मार्ट क्लास ले जाया जाता है, वहां हम ऑडियो विजुअल कंटेंट के माध्यम से सारी जानकारी हासिल करते हैं और सीखते हैं। मुख्यमंत्री ने ऑडियोविजुअल क्लास भी देखी। एक बच्चे प्रदीप चंद्राकर ने ऑडियोविजुअल क्लास के माध्यम से बच्चे को फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की तारीफ की और कहा कि इस तरह से पढ़ने और सीखने की प्रक्रिया बच्चों के लिए बहुत आनंददायी हो जाती है। मुख्यमंत्री बच्चों के अभिभावकों से भी मिले अभिभावकों ने कहा कि यहां पढ़ाई नि:शुल्क है। इतनी अच्छी सुविधाएं हैं टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हमें अपने बच्चों को यहां भेज कर बहुत अच्छा लग रहा है मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से भी चर्चा की और उनकी प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि स्कूल का निर्माण दो करोड़ रुपए की लागत से किया गया है यहां पर बच्चों की शैक्षणिक सुविधा के साथ ही प्लेग्राउंड भी है और बच्चों की खेल संबंधी सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बताया स्कूल में शिक्षकों की समुचित व्यवस्था की गई है साथ ही बच्चों के विकास के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इस मौके पर संसदीय सचिव विनोद सेवन लाल चंद्राकर, पूर्व विधायक श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर सहित अनेक जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे।

आर.एन.आई. रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.